राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

क्रांति समय

सुरत गुजरात से प्रकाशित, मुंबई,उत्तरप्रदेश,बिहार,राजस्थान,मध्यप्रदेश,उतरांचल,उतराखंड,दिल्ली,हरियाणा में प्रसारीत

क्रांति समय
SURESH MAURYA
(Chief Editor)
M. 98791 41480
Working. off.: STPI-SURAT, GUJARAT-395023
(Software Technology Park of India, Surat.
www.krantisamay.com
www.krantisamay.in
krantisamay@gmail.com

सुरत–गुजरात,संस्करण शनिवार,19जून–2021 वर्ष–4, अंक –146पृष्ठ–08 मूल्य–01रूपये

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

बाजारों में उमड़ रही भीड़ का दिल्ली हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान, कहा- कोविड नियमों के उल्लंघन से तेज हो जाएगी तीसरी लहर

नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राजधानी के विभिन्न बाजारों में कोविड-19 प्रोटोकॉल के उल्लंघन का संज्ञान लिया और कहा कि इस तरह के उल्लंघन केवल कोरोना की तीसरी लहर को तेज करेंगे, जिसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है। हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार को इस संबंध में सख्त कदम उठाने, दुकानदारों को जागरूक करने और बाजारों और विक्रेता संघों के साथ बैठक करने को कहा है। जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस आशा मेनन की अवकाश पीठ ने एम्स के एक डॉक्टर द्वारा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों में से एक को भेजी गई कुछ तस्वीरों पर ध्यान दिया, जो बाजारों में रेहड़ी-पटरी वालों द्वारा COVID-19 प्रोटोकॉल की अनदेखी को दिखाती हैं। बेंच ने कहा कि हमने दूसरी लहर में एक बड़ी कीमत चुकाई है। हमें नहीं पता कि क्या ऐसा कोई घर है, जो दूसरी लहर में निकट या दूर से पीड़ित नहीं हुआ है। लॉकडाउन में ढील दिए जाने के बाद दिल्ली के बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर बगैर मास्क के लोगों के घूमने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर बगैर मास्क के घूम रहे लोगों की वायरल हो रही तस्वीरों पर स्वत संज्ञान लेते हुए या आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकारों से यह बताने के लिए कहा है लॉकडाउन खोलने के बाद कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए जारी नियम प्रोटोकॉल का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है? हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार को कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए और सख्त कदम उठाने की जरूरत है। कोर्ट ने केंद्र और दिल्ली सरकार से कहा है कि वह सुनिश्चित करें कि बाजारों में वह सार्वजनिक जगहों पर लोग बगैर मास्क के नहीं घूमें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के साथ ही कोरोना नियमों का पालन करें। पिछले कई दिनों से नए मामलों में गिरावट के बावजूद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शनिवार को आगाह किया कि कोविड महामारी की तीसरी लहर की आशंका काफी वास्तविक है और उनकी सरकार इसका मुकाबला करने के लिए युद्ध स्तर पर तैयारी कर रही है।

राहुल नेतृत्व करने में असमर्थ...

अब असम तक पहुंची कांग्रेस कलह की आंच, विधायक ने पार्टी पर लगाए गंभीर आरोप

नई दिल्ली। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद अब कांग्रेस के भीतर घमासान की आंच असम तक पहुंच गई है। असम के कांग्रेस विधायक ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाकर इस्तीफा देने की बात कही है। असम के कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान अपने युवा नेताओं की बजाय बुजुर्ग नेताओं को प्राथमिकता देता है और इसी वजह से सभी राज्यों में पार्टी की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वह नेतृत्व करने में समक्ष नहीं हैं। पंजाब और राजस्थान कांग्रेस में कलब के बीच असम से कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कहा कि कांग्रेस अपने युवा नेताओं की नहीं सुन रही है। इसलिए सभी राज्यों में इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा और अपना इस्तीफा दे दूंगा। राहुल गांधी नेतृत्व करने में असमर्थ हैं, अगर वह पार्टी के शीर्ष पर रहते हैं तो कांग्रेस आगे नहीं बढ़ेगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं कांग्रेस छोड़ रहा हूं क्योंकि दिल्ली में आलाकमान और गुवाहाटी के नेता बुजुर्ग नेताओं को ही प्राथमिकता देते हैं। हमने उनसे कहा था कि कांग्रेस के पास इस बार सत्ता में आने का अच्छा मौका है और हमें एआईयूडीएफ के साथ गठबंधन नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक गलती होगी और वास्तव में यही हुआ।

बता दें कि पंजाब कांग्रेस में रार अब भी जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। वहीं राजस्थान में भी पायलट गुट और गहलोत गुट के बीच विवाद चल ही रहा है। मुंबई कांग्रेस में भी आपसी कलह की खबर है क्योंकि पार्टी के एक विधायक जीशान सिद्दीकी ने मुंबई कांग्रेस के चीफ भाई जगताप के खिलाफ सोनिया गांधी को लेटर लिखा है।

● असम के कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान अपने युवा नेताओं की बजाय बुजुर्ग नेताओं को प्राथमिकता देता है और इसी वजह से सभी राज्यों में पार्टी की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी, क्योंकि वह नेतृत्व करने में समक्ष नहीं हैं।

दिल्ली दंगे के तीन आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, चार हफ्ते बाद होगी अगली सुनवाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली दंगा मामले में तीन आरोपियों की जमानत के खिलाफ दिल्ली पुलिस की याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की याचिका पर नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ तन्हा को नोटिस जारी किया लेकिन हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल हाई कोर्ट के इस आदेश का हवाला देकर देश की किसी कोर्ट में कोई अभियुक्त आरोपी राहत नहीं मांग सकेगा। मामले की अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से तीनों अभियुक्तों को जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया कि जमानत पर बाहर आ चुके तीनों अभियुक्त फिलहाल बाहर ही रहेंगे।

भारत के तीन राज्यों में महसूस किए गए झटके

रिक्टर स्केल पर 2.6 से 4.1 तक मापी गई तीव्रता

नई दिल्ली। भारत के तीन राज्यों में शुक्रवार को भूकंप के झटके महसूस किए गए। तीनों राज्यों में भूकंप के झटके अलग-अलग समय पर आए। रिक्टर स्केल पर भूंकप की तीव्रता 4.1, 3.0 और 2.6 मापी गई है। 4.1, 3.0 और 2.6 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके क्रमशः सोनितपुर (असम), चंदेल (मणिपुर), पश्चिम खासी हिल्स (मेघालय) में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के मुताबिक, पश्चिम खासी हिल्स (मेघालय) में भूकंप के झटके सुबह 4.20 बजे महसूस किए गए। यहां भूकंप की तीव्रता सबसे कम 2.6 मापी गई। सोनितपुर (असम) में तड़के 2.40 बजे भूकंप आया, यहा तीव्रता तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा 4.1 मापी गई। वहीं चंदेल (मणिपुर) में देर रात 1.06 बजे भूकंप के झटके महसूस किए गए, यहां तीव्रता 3.0 मापी गई है।

4.1, 3.0 और 2.6 की तीव्रता वाले भूकंप के झटके क्रमशः सोनितपुर (असम), चंदेल (मणिपुर), पश्चिम खासी हिल्स (मेघालय) में महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी ने भूकंप की पुष्टि की है।

WHO और AIIMS के सर्वे में दावा

कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का एडल्ट के मुकाबले बच्चों पर ज्यादा असर नहीं होगा

नई दिल्ली। कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर का बच्चों पर ज्यादा असर नहीं होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने अपने सीरोप्रेवैलेंस सर्वे में इस बात का दावा किया है। कोरोना के खतरनाक वैरिएंट को देखते हुए भारत में तीसरी लहर की आशंका व्यक्त की जा रही है, लेकिन अब नए अध्ययन में WHO और AIIMS का दावा राहत देने वाला है। सर्वे के मुताबिक, एडल्ट के मुकाबले SARS-CoV-2 सिरोपॉजिटिविटी रेट बच्चों में अधिक मिली है। सिरोपॉजिटिविटी वायरस के प्रति नेचुरल इम्युन रिस्पॉन्स को माउंट करने की शारीरिक क्षमता बताती है। दिल्ली एम्स में कम्युनिटी मेडिसिन के प्रोफेसर पुनीत मिश्रा ने बताया कि दक्षिणी दिल्ली के शरणार्थी कॉलोनियों में सीरोप्रिवैलेंस 74.7 प्रतिशत काफी ज्यादा पाया गया। ये आंकड़ा अब तक हुए किसी भी सीरो सर्वे में सबसे ज्यादा है। सर्वे के मुताबिक, दूसरी लहर से पहले भी दक्षिणी दिल्ली में रहने वाले 18 साल से छोटे बच्चों में सीरोप्रिवैलेंस 73.9 प्रतिशत था। ज्यादा सीरोप्रिवैलेंस तीसरी लहर के खिलाफ बच्चों पर कवच का काम करेगी।

पांच राज्यों से 10 हजार सैंपल लिए गए-इस सर्वे के लिए 5 राज्यों से 10 हजार सैंपल लिए गए थे। फिलहाल जो रिपोर्ट आई है इसमें 4 राज्यों के 4500 सैंपल को आधार बनाया गया है। अगले दो-तीन महीने में पांचों राज्य के 10 हजार सैंपल साइज की पूरी रिपोर्ट आ जाएगी। यह स्टडी दिल्ली शहरी, दिल्ली ग्रामीण, भुवनेश्वर, गोरखपुर और अगरतला की साइट के लिए औसत आयु 11 वर्ष, 12 वर्ष, 11 वर्ष, 13 वर्ष और 14 वर्ष थी। स्टडी के लिए डेटा 15 मार्च 2021 और 10 जून 2021 के बीच इकट्ठा गया था। शोधकर्ताओं के अनुसार SARS-CoV-2 के खिलाफ कुल सीरम एंटीबॉडी का आकलन करने के लिए एलिसा किट का उपयोग किया गया था। इस किट से मानव शरीर में कोरोना वायरस के एंटीबॉडी की मौजूदगी का पता लगेगा।

ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ जड़ने वाले शख्स की मौत, परिवार ने मर्डर बताया

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में 2015 में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को जिस शख्स ने थप्पड़ जड़े थे, उसकी मौत हो गई है। अभिषेक बनर्जी को कभी थप्पड़ जड़ने वाले भाजपा से जुड़े देबाशीष आचार्य की गुरुवार को रहस्यमय ढंग से मौत हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ अज्ञात लोगों ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया और कुछ देर बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिवार ने इसे हत्या करार दिया है। गुरुवार तड़के देवाशीष आचार्य को गंभीर रूप से घायल हालत में मिदनापुर के तमलुक जिला अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल के रिकॉर्ड से पता चलता है कि उन्हें कुछ अज्ञात लोगों द्वारा सुबह 4.10 बजे लाया गया, जो जल्द ही चले गए। उनकी मौत दोपहर में हुई। जब उनके परिवार को अस्पताल पहुंचने पर रहस्यमय मौत के बारे में पता चला और तो उन्होंने दावा किया कि देवाशीष की हत्या कर दी गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, बीजेपी नेताओं ने अब देवाशीष आचार्य की मौत पर सवाल उठाए हैं। बता दें कि देवाशीष 2020 में भाजपा में शामिल हुए थे। पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में पाया कि देवाशीष आचार्य 16 जून की शाम अपने दो दोस्तों के साथ बाहर गए थे। वह चाय की दुकान पर भी रुके थे और वहां से अचानक चले गए थे। बता दें कि देबाशीष आचार्य सबसे पहले 2015 में उस दौरान सुर्खियों में छाए थे जब उन्होंने एक राजनीतिक कार्यक्रम में अभिषेक बनर्जी को भरी जनसभा में थप्पड़ जड़ दिया था। हालांकि, इसके बाद टीएमसी समर्थकों ने उनकी खूब पिटाई की थी। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार भी किया था, मगर अभिषेक बनर्जी के दखल पर रिहा कर दिया गया था।

राम जन्मभूमि जमीन खरीद विवाद : काशी मॉडल बचा सकता है फजीहत से

अयोध्या। राममंदिर के विस्तारीकरण के लिए भूमि व भवन खरीदने की श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की प्रक्रिया पर उठ रहे सवालों पर विराम लगाने के लिए काशी मॉडल को बेहतर विकल्प माना जा रहा है। काशी मॉडल मे किसी को जमीन लेने से पहले मूल्यांकन समिति अपनी रिपोर्ट देती थी। समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही जमीन का मोलभाव करके सौदा तय होता था। काशी मॉडल को अंजाम देने वाले तत्कालीन वाराणसी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल सिंह अब यहां नगर आयुक्त और अयोध्या विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। उनका कहना है कि यहां आने से पहले शीर्ष स्तर पर अयोध्या में ऐसा ही तरीका अपनाने की चर्चा हुई थी। बताते हैं कि काशी मॉडल पूरी तरह पारदर्शी

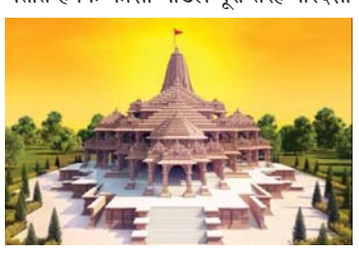

और नियमों के तहत था, किसी की जमीन लेने से पहले मूल्यांकन समिति अपनी रिपोर्ट देती थी। इसमें एसडीएम, सब रजिस्ट्रार, तहसीलदार-कानूनगो और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर शामिल होते थे। इनकी रिपोर्ट पर निगोसिएशन समिति बातचीत करके अनुमोदन करती थी। इस तरह से ट्रस्ट भी प्रशासन से मूल्यांकन कराकर किरकिरी से बच सकता है। इस बीच, हाल की घटनाओं से ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के आसपास घेरा बनाने की कोशिश करने वाले तमाम प्रॉपर्टी के दलाल अब गायब हो गए हैं। संघ-विहिप के धुर विरोधी द्वारिका व शारदापीठाधीश्वर जगदगुरु शंकराचार्य स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती के रामालय ट्रस्ट के सचिव स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद काशी से अयोध्या आकर विरोधी संतों को एकजुट कर रहे हैं। वहीं रामजन्मभूमि विवाद में पक्षकार रहे अनी अखाड़ा के महंत धर्मदास भी अपनी उपेक्षा से 'आग में घी' डालने में जुटे हैं। वक्फ की संपत्ति बहाली में बाबरी एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों की सक्रियता भी दिख रही है। ऐसे में सबसे अहम रामजन्मभूमि के पीछे कटरा इलाके के तमाम मुस्लिमों से चल रही उनकी भूमि-भवन की खरीद संबंधी बातचीत में अब काशी मॉडल की जरूरत महसूस की जा रही है।

राजस्व रिकॉर्डों की जांच होती तो फजीहत से बच जाता ट्रस्ट

श्री रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट स्वायत्तशासी होने के साथ केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों से भी युक्त है। इसमें गृह मंत्रालय के विशेष सचिव पदेन केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

कोरोना-गुजरात की साबरमती नदी में मिला कोविड-19 वायरस, सभी नमूने संक्रमित

नई दिल्ली। अभी तक देश के कई शहरों में सीवेज लाइन में कोरोना वायरस के जीवित मिलने की पुष्टि हो चुकी है लेकिन पहली बार प्राकृतिक जल स्त्रोत में भी कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला है। गुजरात के अहमदाबाद की लाइफलाइन कहे जाने वाली साबरमती नदी में कोरोना वायरस मिला है। यहां से लिए सभी सैंपल संक्रमित मिले हैं। साबरमती के साथ ही अहमदाबाद के अन्य जल स्त्रोत कांकरिया, चंदोला झील से लिए गए सैंपल भी संक्रमित मिले हैं। इतना ही नहीं शोद्यार्थियों ने जब असम के गुवाहाटी क्षेत्र में भी नदियों की जांच की तो वहां भारू नदी से लिया एक सैंपल कोरोना संक्रमित मिला है। इन सभी सैंपल में विषाणुओं की मौजूदगी काफी अधिक बताई गई है। आईआईटी गांधी नगर सहित देश के आठ संस्थानों ने मिलकर यह अध्ययन किया है जिसमें नई दिल्ली स्थित जेएनयू के स्कूल ऑफ इनवॉयरमेंटल साइंसेज के शोद्यार्थी भी शामिल हैं।

गांधीनगर स्थित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के पृथ्वी विज्ञान विभाग से मनीष कुमार ने बताया कि पिछले वर्ष सीवेज से सैंपल लेकर जांच के दौरान कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चला था। इस अध्ययन के बाद प्राकृतिक जल स्त्रोत के बारे में भी पता लगाने के लिए दोबारा अध्ययन शुरू किया गया। चूंकि अहमदाबाद में सबसे ज्यादा वेस्ट वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं और गुवाहाटी में एक भी प्लांट नहीं है। इसलिए इन दोनों शहरों का चुनाव करते हुए सैंपलिंग शुरू की गई।

मार्च तक गुवाहाटी में करते रहे जांच

शोधार्थियों ने बताया कि साबरमती से सभी संक्रमित सैंपल मिलने के बाद गुवाहाटी में काम शुरू किया गया। मार्च तक यहां सैंपलिंग और जांच चलती रही और उस दौरान भारू से लिए नदी में सैंपल संक्रमित मिले हैं। हालांकि ब्रह्मपुत्र नदी को लेकर आशंका कम है। एक मानना यह भी है कि वहां कोरोना के मामले कम होने के चलते भी ऐसा हो सकता है।

सभी प्राकृतिक जल स्त्रोत की जांच जरूरी-मनीष के मुताबिक तीन सितंबर से 29 दिसंबर 2020 तक हर सप्ताह सैंपल लेने के बाद जांच की गई और इसमें की काफी मौजूदगी पाई गई। साबरमती से 694, कांकरिया से 549 और चंदोला से 402 सैंपल लिए गए जो जांच में संक्रमित पाए गए।

इससे साफ पता चलता है कि वायरस प्राकृतिक जल में भी जीवित रह सकता है। इसलिए देश के सभी प्राकृतिक जल स्त्रोत की जांच होनी चाहिए क्योंकि दूसरी लहर में वायरस के कई गंभीर म्यूटेशन भी देखने को मिले हैं।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

संपादकीय

न्यायपूर्ण परिणाम

कोरोना के दौर में प्रत्यक्ष पढ़ाई और परीक्षा के अभाव में बच्चों को उत्तीर्ण करने का जो तरीका मंजूर हुआ है, समग्रता में उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। परीक्षा परिणाम निकालने का यह फॉर्मूला भविष्य में भी हमारे काम आएगा। आशा के अनुरूप ही 12वीं कक्षा का परिणाम 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षा में प्रदर्शन के आधार पर जारी किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी और सुप्रीम कोर्ट ने इस तरीके को मान लिया। 10वीं और 11वीं के अंकों को 30-30 प्रतिशत वेटेज और 12वीं कक्षा में प्रदर्शन को 40 प्रतिशत वेटेज दिया जाएगा। यह तरीका तार्किक है, इसके आधार पर छात्रों का बहुत हद तक न्यायपूर्ण आकलन किया जा सकता है। वैसे यह बात सही है कि ज्यादातर छात्र फाइनल परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन करने का इंतजार करते हैं। इस मामले में 10वीं की परीक्षा के परिणाम का महत्व कुछ ज्यादा हो सकता था, क्योंकि 10वीं की परीक्षा के प्रति ज्यादातर छात्रों में बहुत गंभीरता होती है। 10वीं की तुलना में 11वीं की परीक्षा का विशेष महत्व नहीं होता है। ज्यादातर छात्रों में यह प्रवृत्ति होती है कि वे फाइनल परीक्षा को गंभीरता से लेते हैं। अत- परिणाम निकालने का कोरोना-काल का यह सलीका छात्रों के लिए सबक होना चाहिए। जब प्रत्यक्ष कक्षाएं नहीं लगेंगी, जब प्रत्यक्ष परीक्षाएं नहीं होंगी, तब हर कक्षा और हर छोटी-बड़ी परीक्षा का महत्व बढ़ जाएगा। हर परीक्षा भविष्य पर असर डालेगी। अब 31 जुलाई तक सीबीएसई द्वारा 12वीं के नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे और उसके बाद उच्च व व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में भी प्रवेश में तेजी आएगी। प्रतियोगी परीक्षाओं का क्रम तेज होगा, जिससे समग्र शिक्षा क्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी। एक खास बात यह भी है कि 10वीं के पांच में से श्रेष्ठ तीन विषयों के अंकों के आधार पर आकलन किया जाएगा। यह उदार फैसला पूरी तरह से छात्रों के अनुकूल है। सीबीएसई या सरकार से यही उम्मीद थी कि वह संकट के दौर में छात्रों के प्रति उदारता बरतेगी। आगे के समय में भी यह ध्यान रखना होगा कि ऐसे परिणाम से गुजरे छात्रों के प्रति नाइंसाफी न हो। एक जुमला इन दिनों चलन में आने लगा है 'कोरोना बैच'। इसके उपयोग या चलन से बचना चाहिए। जिन छात्रों को ऐसे परिणाम से गुजरना पड़ा, उनकी कोई गलती नहीं थी, अत- उनकी चिंता सरकार को आगे भी करनी पड़ेगी। वैसे भी जो बच्चे परिणाम से संतुष्ट नहीं होंगे, उन्हें हालात सामान्य होने पर दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। लगे हाथ अदालत ने यह साफ कर किया है कि परीक्षा रद्द करने के आदेश पर कोई सुनवाई नहीं होगी। यदि कोई परीक्षा देना चाहता है, तो आगे दे सकता है। प्रत्येक स्कूल को तीनों परीक्षाओं में छात्रों को मिले अंकों पर विचार करने के लिए एक परिणाम समिति बनानी पड़ेगी, जिसे सीबीएसई की मॉडरेशन कमेटी द्वारा जांचा जाएगा। उम्मीद है, सभी राज्यों की बोर्ड परीक्षाएं भी रद्द हो जाएंगी और सुप्रीम कोर्ट द्वारा मंजूर फॉर्मूले के आधार पर ही उनसे संबद्ध छात्रों को परीक्षा परिणाम दे दिए जाएंगे। हालांकि, राज्य बोर्डों की परीक्षा रद्द करने के आग्रह वाली याचिका पर सुनवाई होने वाली है। कुल मिलाकर, सरकार और सुप्रीम कोर्ट ने अपना काम कर दिया है, अब स्कूलों को निष्पक्ष और न्यायपूर्ण ढंग से परिणाम निकालने के इस तरीके को सफल बनाना चाहिए।

'आज के ट्वीट

पद्मश्री सम्मान से सम्मानित

तमिलनाडु के कोयंबटूर में रहने वाली 106 वर्षीय आर पम्पममल ने जैविक खेती को एक नई दिशा प्रदान की है। उन्होंने अपने कार्यों से महिला किसान के रूप में अपनी सफलता की कहानी लिखी है। भारत सरकार ने उनके कार्यों को देखते हुए उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया है।

-- डॉ. विवेक बिन्द्रा

दोस्ती का हाथ बढ़ते अमेरिका और रूस

सियाराम पांडेय 'शांत'

संवाद की अपनी ताकत है। संवाद हमेशा सफल हो, जरूरी नहीं लेकिन उसकी विफलता भी संभावनाओं का संसार तो रचती ही है। जेनेवा के लेकसाइड विला में चार घंटे में अमेरिका और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच दो चरणों में हुई वार्ता का लब्बोलुआब भी यही है। इस शिखर वार्ता में दोनों देशों के बीच की कड़वाहट जहां घाटी है, वहीं दोनों देश अपने-अपने राजदूत एक-दूसरे की राजधानियों में भेजने को सहमत हो गए हैं, इसे किसी उपलब्धि से कमतर नहीं आंका जा सकता। इस साल के प्राम्भ में दोनों देशों ने अपने राजदूत बुला लिए थे। इस शिखर बैठक में अगर मानवाधिकार के मुद्दे उठे तो परमाणु हथियारों की तरह साइबर हमलों पर भी चर्चा हुई। खुद पुतिन भी मानते हैं कि इस बैठक से दोनों देशों के रिश्तों में जितना सुधार हो लेकिन परस्पर विश्वास की उम्मीद तो बनी ही है। दो महाशक्तियां अगर एक-दूसरे पर विश्वास करें तो भी अन्य छोटे और मंझोले देशों का फायदा ही होता है। उनकी जंग में वे अनावश्यक पिसने से बच जाते हैं। एक दशक बाद ही सही, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमिर पुतिन का जेनेवा में वार्ता की मेज पर होना अपने आप में बड़ी घटना है। उससे भी बड़ी बात कि इसमें पहले जैसा पूर्वाग्रह नहीं, गर्मजोशी भर उदार रवैया देखने को मिला। दोनों देश जानते हैं कि दोनों के अपने व्यापारिक और सामरिक हित हैं। दुनिया के बाजारों में दोनों को अपने हथियार बेचने हैं। इसके लिए उन्हें किसी देश का साथ देना और किसी की मुखालफत भी करनी है। ऐसा करते हुए अमेरिका और रूस में कड़वाहट बढ़ सकती है लेकिन उनमें प्रबल टकराव न हो, इस बात की गुंजाइश और पारस्परिक समझ तो संवाद से ही विकसित होगी। 10 मार्च 2011 को मास्को में जब दोनों मिले थे तो उस समय उनमें कोई भी राष्ट्रपति नहीं था। तब बाइडेन अमेरिका के उपराष्ट्रपति और पुतिन रूस के प्रधानमंत्री हुआ करते थे। यह और बात है कि इस मुलाकात से पूर्व पुतिन 1999 से 2008 तक रूस के राष्ट्रपति रह चुके थे। जिस दौर में बाइडेन की उनसे मुलाकात हुई थी, उस समय वे रूस के प्रधानमंत्री थे। 20 जनवरी 2021 को अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन की पुतिन के साथ यह पहली मुलाकात थी। कहना न होगा कि इस मुलाकात की पहल भी बाइडेन की ओर से ही की गई थी। दस साल में जाहिर है, बहुत कुछ बदल गया है लेकिन यह मुलाकात इस बात का संदेश तो है कि विश्व की दोनों महाशक्तियों के बीच तनातनी का खेल बहुत हो चुका, अब तो इस पर बस अर्थात विराम की ही जरूरत है। वैसे जिस तरह बाइडेन ने पुतिन को काबिल विरोधी कहा है और पुतिन ने चीन और डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की है, उससे दोनों वैश्विक नेताओं की तल्खी का तो पता चलता ही है। यह और बात है कि विगत कुछ वर्षों में अमेरिका और रूस के बीच बढ़ी खटास की एक वजह अमेरिकी चुनाव भी रहा है। इस बैठक से एक दिन पहले बाइडन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन में शामिल रहे अधिकारियों समेत रूसी विशेषज्ञों के एक समूह से बैठक की थी। बैठक में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा के कार्यकाल के दो पूर्व रूसी राजदूत माइकल मैकफॉल और जॉन टेफ्ट समेत करीब 12 विशेषज्ञ शामिल हुए थे। 14 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कहेंगे कि वाशिंगटन मास्को के साथ संघर्ष की तलाश नहीं कर रहा है लेकिन उसकी हानिकारक गतिविधियों का जवाब अवश्य देगा। इस बैठक की एक वजह चीन और रूस के बीच बढ़ते सहयोग पर अमेरिका की चिंता भी है। यह और बात है कि वे पुतिन के साथ वार्ता करते हुए बहुत तल्ख नहीं रह पाए। चीन और रूस की नजदीकियों पर भी वे ब्रेक लगा पाए हैं, ऐसे कोई संकेत नहीं मिले। हाल के एक दशक में जिस तरह चीन और रूस की नजदीकियां बढ़ी है और उनके रिश्ते अर्ध-गठबंधन जैसी शक्ल अख्तियार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र में महत्वपूर्ण मुद्दों पर रूस और चीन की परस्पर जुगलबंदी नजर आती है। दोनों देश व्यापार, सैन्य और तकनीकी क्षेत्र में आपसी सहयोग बढ़ा रहे हैं, उससे अमेरिका की पेशानियों पर बल तो पड़े ही हैं। अमेरिकी एजेंसियों और निजी कंपनियों पर किए गए साइबर हमले के लिए भी रूसी राष्ट्रपति को ही जिम्मेदार ठहराया जाता रहा है। पुतिन के घोर विरोधी नेता एलेक्सी नवलनी के साथ जो कुछ हुआ, उसको लेकर अमेरिका समेत कई देश रूस के खिलाफ रहा है लेकिन पुतिन ने साफ कह दिया है कि नवलनी की जगह जेल ही है। पुतिन ने तो यहां तक कह दिया की सियासी विरोधियों से निपटने के लिए क्या अमेरिका में कानून नहीं है। दोनों देशों के बीच हथियार एक बड़ा मुद्दा है। अमेरिका नहीं चाहता है कि रूस की प्रणाली एस 400 को कोई देश खरीदे। इसे लेकर वह अन्य देशों पर दबाव भी डालता रहा है। तुर्की और भारत भी इसके अपवाद नहीं हैं। यह और बात है कि रूस से पुराने संबंधों और अपनी रक्षा जरूरतों का वास्ता देकर दोनों ही देश अमेरिकी दबाव मानने से इनकार कर चुके हैं। सीरिया में पुतिन का सरकार को समर्थन और वहां ताबड़तोड़ हमले, सीरियाई फौज को मदद करना कभी भी अमेरिका को रास नहीं आया। यूक्रेन और लीबिया में भी कुछ ऐसा ही है। बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के कूटनीतिक संबंध बहुत हद तक खराब हुए हैं। बाइडेन के पास अगर आरोपों का अंबार तो था लेकिन पुतिन से वे कितने मुद्दों पर चर्चा कर पाए, यह अभी स्पष्ट नहीं है। इतना तो पुतिन भी जानते हैं कि अमेरिका महामारी के दौर में रूस और चीन की चुनौतियों का एक साथ मुकाबला करने की हालत में नहीं है। वर्ष 2014 में जब रूस ने ताकत के बल पर क्रीमिया पर कब्जे की कोशिश की थी तभी से अमेरिका और रूस के बीच रिश्ते खराब होने शुरू हो गए थे। 2016 में अमेरिका में हुए राष्ट्रपति चुनाव में तो यह तनातनी चरम पर पहुंच गई। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने आरोप लगाया कि रूस डोनाल्ड ट्रम्प और रिपब्लिकन पार्टी की मदद कर रहा है। यही नहीं, रूस की गुप्तचर एजेंसियों पर चीन के साथ मिलकर अमेरिका की अहम कंपनियों का डेटा चुराने की कोशिश करने का आरोप भी लगा। यह और बात है कि रूस ने इन तमाम आरोपों को न तो कभी स्वीकार किया और न ही अमेरिका ने कभी अपने आरोपों के पक्ष में कोई सबूत प्रस्तुत किए। बाइडेन ने मार्च में अपने एक साक्षात्कार में पुतिन को हत्यारा कहा था। इस पर पुतिन ने बाइडेन को खुली बहस की चुनौती दी थी। साथ ही अमेरिका को 'अनफ्रेंडली कंट्री' लिस्ट में डाल दिया था। रूस ने वॉशिंगटन से अपने राजदूत को वापस बुला लिया। कुछ दिन बाद मॉस्को ने अमेरिकी एम्बेसडर जॉन सुलिवान को देश छोड़ने के आदेश दिए। कई और अफसरों को दोनों देशों ने निकाला। अब इस तनातनी की जद में बहुराष्ट्रीय कंपनियां भी आ गई हैं। यह और बात है कि बाइडेन ने अप्रैल में पुतिन को फोन किया और बातचीत का न्योता दिया। इसके बाद यह मुलाकात हुई। अमेरिका चाहता है कि रूस अब चीन पर यह दबाव डाले कि वह कोरोना ओरिजिन पर सबूत और मेडिकल डॉक्यूमेंट्स साझा करे। इसके अलावा हॉन्गकॉन्ग, ताइवान और दक्षिण चीन सागर में चीन की हरकतों को रोके। रूस ने अबतक कोरोना ओरिजिन पर चीन के पक्ष में ही दलीलें दी हैं। अमेरिका यह भी चाहता है कि ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने के लिए रूस उसकी पहल का हिस्सा बने लेकिन लगता नहीं कि बाइडेन को इस मामले पर कामयाबी मिली है क्योंकि रूस अपने हित देख रहा है। अमेरिका की तरफ से 32 रूसी संस्थाओं पर लगाए गए बैन, 2020 के चुनाव में रूस का शामिल होना और यूएस नेटवर्क की सप्लाई चेन सॉफ्टवेयर हैंकिंग जैसे मुद्दे हैं। जबकि रूस इन आरोपों को नकारता रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हाल ही में स्टेट डिपार्टमेंट में क्लाइमेट चेंज सपोर्ट ऑफिस शुरू करने के आदेश दिए हैं। इसका उद्देश्य जलवायु परिवर्तन को लेकर उठाए जा रहे प्रयासों का समर्थन करना है। दोनों देशों के बीच वार्ता का जो सिलसिला आरम्भ हुआ है, वह आगे भी चलेगा। दोनों देशों ने जिस तरह वार्ता के लिए अपने अधिकारियों को भेजने पर सहमति जताई है, वह एक अच्छा संकेत है।

यद्यपि कि दोनों देशों के अपने हित हैं और हितों से समझौता कोई नहीं करना चाहेगा। पैंतरे पर रहकर वार्ता वैसे भी नहीं होती लेकिन वार्ता हुई है तो दूर तक जाएगी।अमेरिका और रूस अगर दोस्ती का हाथ बढ़ते हैं और रिश्तों को मजबूती देते हैं तो इससे भारत को भी फायदा होगा क्योंकि दोनों ही से उसके अपने संबंध हैं।

(लेखक हिन्दुस्थान समाचार से सम्बद्ध हैं।)

ज्ञान गंगा

रिश्ते

जग्गी वासुदेव

अगर आप एक रिश्ता तोड़ कर बाहर आ रहे हैं, तो अपने आपको पर्याप्त समय दीजिए। आप अपने लिए कम से कम 6 महीने या 1 साल का समय रखिए जिसमें आप सिर्फ अपने आप में ही रहेंगे क्योंकि जो कुछ भी गलत हुआ, उसमें आपका 50त्न योगदान निश्चित है, है कि नहीं? तो इन 6 महीनों या 1 साल का उपयोग उस गड़बड़ी को ठीक करने में करिए। जब आपके दरवाजे पर जीवन इस तरह से दस्तक दे तो ये कुछ गहराई से देखने का समय है। जब आपके भ्रम टूट जाते हैं और आप इस समय पर यह साफ-साफ देख पा रहे हैं तो यह बहुत अच्छी बात है। अगर आपके भ्रम टूट गए हैं तो इसका मतलब है कि जीवन आपको वास्तविकता के करीब ला रहा है। आपके पास अवसर है कि आप बैठें और सोचें, 'मेरे जीवन का स्वभाव क्या है'? जब कोई आपको एक भ्रम की अवस्था में से वास्तविकता की ओर धकेल रहा है, तो आपको उस व्यक्ति को धन्यवाद देना चाहिए कि वो आपके लिए एक आध्यात्मिक आयाम खोल रहा है, यह बताते हुए कि ये सब बातें कितनी नाजुक, कमजोर, अस्थायी हैं! वो आपके साथ धोखा कर सकता है, आपसे दूर भाग सकता है या कुछ और कर सकता है, पर मूल रूप से उसने आपको ठुकरा दिया है। आपको ठुकराया जा सकता है क्योंकि आप भ्रम की अवस्था में हैं और यह विश्वास करते हैं कि आप बस आधे ही जीवन हैं और बाकी आधा और कहीं से आएगा। पर ऐसा नहीं है, आप यह जो जीवन का एक भाग हैं, वो वास्तव में जीवन का पूरा भाग है, जिसमें सृष्टि और सृष्टिकर्ता, दोनों ही भरे हुए हैं-यह एक बढ़िया मेल है, जोड़ है। तो फिर ऐसा क्यों है कि यह अपने आपको अधूरा पाता है और ऐसा महसूस करता है कि जीवन को पूरा करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति की जरूरत है? कहीं न कहीं इसने अपने स्वभाव के पूरेपन को नहीं समझा है। अभी तो आपने इसे ऐसा बना लिया है कि यह इसके या उसके बिना नहीं रह सकता। अगर आप पूरे जीवन के रूप में खिले हों तो आप देखेंगे कि रिश्ते बिल्कुल ही अलग तरीके के होंगे। ये कुछ इस तरह से होंगे कि ज्यादा से ज्यादा साथ में आएं और एक दूसरे के साथ साझा करें। ये उससे कुछ छीन लेने के बारे में नहीं होगा।

आज का राशिफल

मेष जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। रोजी के अवसर बढ़ेंगे। आर्थिक संकट का सामना करना पड़ेगा। किसी मूल्यवान वस्तु के चोरी या खोने की आशंका है। व्यावसायिक मामलों में लाभ मिलेगा।

वृषभ आर्थिक मामलों में सुधार होगा। यात्रा देशाटन की स्थिति सुखद व लाभप्रद होगी। मांगलिक उत्सव में भाग लेंगे। राजनैतिक महत्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी।

मिथुन पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। किसी कार्य के सम्पन्न होने से आपके प्रभाव तथा वर्चस्व में वृद्धि होगी। संतान या शिक्षा के कारण चिंतित हो सकते हैं। रचनात्मक प्रयास फलीभूत होंगे।

कर्क आर्थिक पक्ष मजबूत होगा। शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में आशातीत सफलता मिलेगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। दूसरों से सहयोग लेने में सफल होंगे। विभागीय समस्या आ सकती है।

सिंह पारिवारिक जनों के साथ सुखद समय गुजरेगा। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे। रुपए पैसे के लेन-देन में सावधानी रखें। किसी रिश्तेदार के कारण तनाव हो सकता है।

कन्या जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। आय के नए स्त्रोत बनेंगे। उदर विकार या त्वचा के रोग से पीड़ित रहेंगे। मांगलिक उत्सव में हिस्सेदारी होगी। वाहन प्रयोग में सावधानी रखें।

तुला प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। किया गया श्रम सार्थक होगा। संबंधित अधिकारी के कृपा पात्र होंगे। संतान के संबंध में सुखद समाचार मिलेगा। प्रणय संबंध प्रगाढ़ होंगे।

वृश्चिक दाम्पत्य जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। आय और व्यय में संतुलन बनाकर रखें। राजनैतिक महात्वाकांक्षा की पूर्ति होगी। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। व्यर्थ की भागदौड़ रहेगी।

धनु संतान के दायित्व की पूर्ति होगी। सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। नेत्र विकार की संभावना है। मन अशान्त रहेगा। जीविका के क्षेत्र में प्रगति होगी। स्वास्थ्य एवं प्रतिष्ठा के प्रति सचेत रहें।

मकर पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। संबंधित अधिकारी से तनाव मिलेगा। स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहें। ससुराल पक्ष से लाभ होगा। कोई पारिवारिक व व्यावसायिक समस्या आ सकती है।

कुम्भ जीवन साथी का सहयोग व सानिध्य मिलेगा। किसी अज्ञात भय से ग्रसित रहेंगे। क्रोध व भावुकता में लिया गया निर्णय कष्टकारी होगा। उपहार व सम्मान का लाभ मिलेगा। प्रेम प्रसंग प्रगाढ़ होंगे।

मीन पारिवारिक जीवन सुखमय होगा। धन, पद, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सुखद परिवर्तन की दिशा में व्यक्ति विशेष का सहयोग मिलेगा। पिता या उच्चाधिकारी का सहयोग मिलेगा। रक्तचाप में वृद्धि होगी।

बिहारियों की अपने खानपान को लेकर अद्भुत निष्ठा

आर.के. सिन्हा

बिहार अपने बहुलतावादी समाज, समृद्ध संस्कृति, गौरवशाली इतिहास वगैरह के चलते अति विशिष्ट है। इस राज्य को एक अन्य वजह भी खास बनाती है। वह है बिहारियों की अपने खानपान को लेकर अद्भुत निष्ठा। बिहारी भोजन की मात्रा और गुणवत्ता के सवाल पर कभी समझौता करना पसंद नहीं करते। यह ऐसा बिन्दु है जिस पर बिहार में जाति, धर्म, वर्ग के बंधन टूट जाते हैं। बिहारी को उसका पसंदीदा सुस्वादु भोजन मिल जाए तो वह परम आनंद की स्थिति में होता है। अन्यथा वह सख्त नाराज भी हो जाता है। फिर बात सिरे से बिगड़ भी सकती है। इस बात की पुष्टि हाल ही में देखने-सुनने को मिली। बिहार में विवाह और दूसरे समारोहों में अतिथियों को मछली या मिष्ठान पर्याप्त मात्रा में न मिलने के कारण महाभारत हो गया। जब सारे भारत में कोरोना वायरस से बचने के लिए मास्क और सोशल डिस्टेनसिंग जैसे नियमों का पालन करने का हर स्तर पर आह्वान किया जा रहा है, तब बिहार एक अन्य अहम मसले से जूझ रहा है। अब देखें कि बिहार के गोपालगंज में एक शादी समारोह के दौरान खाने में मछली परोसने को लेकर तगड़ा विवाद हो गया। जिसमें दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। मालूम चला है कि मछली के मुड़े यानी उसके सिर का हिस्सा खाने को लेकर दो पक्षों में खूनी झड़प हुई। इसमें दोनों ही ओर से 11 लोग घायल हुए हैं। स्वादिष्ट भोजन का आकर्षण सारे भारतीयों में रहता है। वे लजीज भोजन पर टूट पड़ते हैं। मौका चाहे विवाह समारोह का हो या कोई अन्य। सबसे पहले और अधिक से अधिक भोजन अपनी प्लेट में भर लेने की कवायद में अच्छे-भले लोग भी कई बार बहुत टुच्ची हरकतें करने लगते हैं। ये सब देखना-सुनना कदापि सुखद नहीं लगता। बिहार के मिथलांचल क्षेत्र में दावत में मछली या मांस का न परोसा जाना मेहमानों को बहुत बुरा लग सकता है। इधर तो भोजन का मतलब ही होता है कि सामिष भोजन तो मिलेगा ही। मिथलांचल का तो ब्राहमण भी सामिष भोजन ही पसंद करता है। मिथलांचल में दरभंगा, मधुबनी, मुंगेर, कोसी, पूर्णिया और भागलपुर प्रमंडल तथा झारखंड के संथाल परगना प्रमंडल के साथ-साथ नेपाल के तराई क्षेत्र के कुछ भाग भी शामिल हैं। बिहारी समाज के स्वादिष्ट व्यजनों के प्रेम पर किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। दिक्कत सिर्फ इतनी है कि बिहारी समाज का कम से कम एक हिस्सा लजीज भोजन न मिलने पर नाराज भी हो जाता है। फिर वह लड़ने-झगड़ने तक लग जाता है। बेशक बिहारी समाज को अपने में बदलाव तो लाना ही होगा। वहां की शादियों में धन की फिजूलखर्ची को रोका जाना चाहिए। वहां पर विस्तृत भोजन परोसने के क्रम में वधू पक्ष को लाखों रुपए की चपत लग जाती है। इसके बावजूद मेहमान नाखुश ही बने रहते हैं। सुनकर भी कितना कष्ट होता है कि गोपालगंज में आई बारात में खाने के लिए बैठे लोगों को पहले राउंड में दो-दो पीस मछली दी गई। जिसके बाद मछली के मुड़े की फरमाइश की गई, जिसे नहीं दिए जाने पर हंगामा बढ़ा। बस इसके बाद ही जमकर मारपीट शुरू हो गई। कुछ मीडिया खबरों पर यकीन करें तो पिछले दिनों राज्य में आई एक बारात में सब्जी को लेकर विवाद में गोलीबारी तक हो गई थी। जिसमें गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। पहले तो यह सवाल स्थानीय प्रशासन से पूछा जाना चाहिए कि जब कोरोना की दूसरी लहर से राज्य और देश हांफ रहा था तब उन्होंने इतने बड़े स्तर पर शादी के आयोजन की अनुमति कैसे दे दी या वहां इतने बड़े स्तर पर विवाह का आयोजन कैसे हो गया ? मूलत: महाराष्ट्र से संबंध रखने वाले लेकिन कई बार बिहार से भी लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए समाजवादी नेता और चिंतक मधु लिमये कहते थे कि उन्होंने बिहारियों से बढ़कर कोई भोजन भट्ट नहीं देखा। वहां पर अगर आप किसी को पूरी-हलवा की दावत के लिए आमंत्रित करें तो वह उफनती कोसी नदी को पार करके आ जाएगा। एकबार बिहारी जब भोजन करने लगता है तो फिर वह भोजन के साथ कायदे से न्याय करता है। बिहारी भोजन करने में पर्याप्त समय भी लेता है। वह चपाती, सब्जी, चावल, मांस, मछली, दही वगैरह की बार-बार मांग करेगा। वह आमतौर पर अल्पाहारी तो बिलकुल नहीं होता। भोजन को बर्बाद नहीं करेगा। यह उसे बचपन से ही घर में सिखाया जाता है कि भोजन को बर्बाद करने से ईश्वर भी नाराज होता है। बिहारी को भोजन के पश्चात मीठा खाना भी पसंद है। अगर उसे भोजन के बाद कोई मनपसंद मिठाई मिल जाए तो वह अपने मेजबान का बहुत कृतज्ञ हो जाता है। उसे लगता है कि मेजबान ने उसका दिल से सम्मान किया है। यहां तक तो सब ठीक है। आखिर स्वादिष्ट भोजन और उसके बाद मिष्ठान कौन नहीं पाना चाहता। सभी तो चाहते हैं कि उन्हें भोजन के बाद कुछ मिठाई मिल जाए। पर यह उचित नहीं माना जा सकता है कि शादी समारोह में मछली कम मिलने पर झगड़ा कर लिया जाए। औसत बिहारी परिवारों की गृहणियों के दिन का बहुत सारा वक्त तो भोजन पकाने और उसकी योजना बनाने में ही गुजर जाता है। मतलब साफ है कि बिहारी अपने घर में भी स्वादिष्ट भोजन करना पसंद करता है। वह घर से बाहर ही स्वादिष्ट भोजन करने की फिराक में नहीं रहता। वह घर में लिट्टी-चोखा बार-बार खाता है। लिट्टी सत्तू और मसाले के मिश्रण से बनती है। जहां तक चोखा की बात है तो आलू और बैंगन (जिसका चोखा बनाना है) को आग में पका लिया जाता है। इसके बाद इसके छिलके को हटाकर उसे नमक, तेल, हरी मिर्च, प्याज, लहसुन इत्यादि के साथ गूंथ लिया जाता है। लिट्टी-चोखा का स्वाद अतुलनीय होता है। इसे तो बिहारी रोज ही खाते या खाना पसंद करते हैं। यह याद रखें कि बिहारी आम के भी रसिया होते हैं। चंपारण जिले (अब तो पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण दो जिले हो गये हैं) की जब भी बात होती है, तब महात्मा गांधी के वहां के नील की खेती करने वाले किसानों के पक्ष में निलहा आन्दोलन का ख्याल तुरंत जेहन में आ जाता है। उस असाधारण आंदोलन के संबंध में आज भी सारा देश पढ़ता है। वहां के जर्दालु आम का स्वाद और खुशबू अद्वितीय होती है। इसे खाने के बाद इंसान एकबार तो कह देता है कि 'इससे बेहतर आम कभी नहीं चखा।' जहां दशहरी, लंगड़ा, मालदह, चौसा, मलिहाबादी, सहारनपुरी, बादामी, तोतापरी, केसर आदि आमों की प्रजातियों से सारा देश परिचित है, जर्दालु आम के बारे में बिहार से बाहर के लोगों को लगभग कोई जानकारी नहीं है। बिहारी इन्हें खूब खाते हैं और इसके कम मिलने पर किसी से लड़ते भी नहीं हैं। कम से कम इस तरह की कोई खबर तो नहीं सुनी। उम्मीद है कि बिहारी स्वादिष्ट भोजन, मिठाई और फलों का स्वाद बिना किसी विवाद के लेते रहेंगे। मेहमान नवाज पसंद बिहारी खाते भी रहेंगे और खिलाते भी रहेंगे ढ्ढ पर झगड़ने से जरूर बचेंगे ढ्ढ

(लेखक वरिष्ठ संपादक, स्तंभकार और पूर्व सांसद हैं।)

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

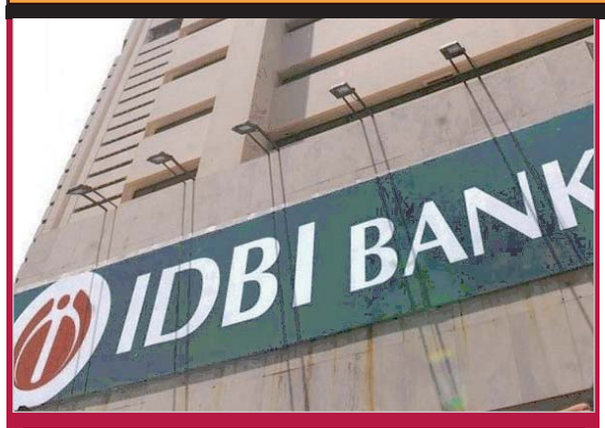

संपत्ति पुनर्गठन कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचेगा आईडीबीआई बैंक

नई दिल्ली: आईडीबीआई बैंक अपनी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लि. (अर्सिल) में अपनी हिस्सेदारी बेचने की योजना बना रहा है। बैंक ने संपत्ति पुनर्गठन कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बेचने के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। आईडीबीआई बैंक ने एक नोटिस में कहा, ''बैंक का इरादा 6,23,23,800 इक्विटी शेयरों की बिक्री करने का है, जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. की कुल इक्विटी शेयर पूंजी का 19.18 प्रतिशत है। रुचि पत्र (ईओआई) जमा कराने की अंतिम तिथि 25 जून है। एलआईसी के नियंत्रण वाले निजी क्षेत्र के बैंक ने कहा कि उसके पास इस प्रक्रिया से बाहर निकलने और किसी पेशकश को बिना कोई वजह बताए स्वीकार करने या खारिज करने का अधिकार रहेगा। अर्सिल का गठन 2002 में हुआ था। एसबीआई, आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, पीएनबी और रणनीतिक विदेशी निवेशक मसलन एवेन्यू इंडिया रिसर्जेंस पीटीई लि. इसमें हिस्सेदार हैं। गठन के बाद से अर्सिल ने करीब 78,000 करोड़ रुपये की गैर-निष्पादित आस्तियों (एनपीए) का समाधान किया है।

शेयरचैट का 1.91 करोड़ डॉलर का इसॉप पुनर्खरीद कार्यक्रम

नई दिल्ली। सोशल मीडिया ऐप शेयरचैट तथा शॉर्ट वीडियो ऐप मोज का परिचालन करने वाली मोहल्ला टेक ने 1.91 करोड़ डॉलर (140 करोड़ रुपए) के कर्मचारी शेयर विकल्प योजना (इसॉप) पुनर्खरीद कार्यक्रम की घोषणा की है। कंपनी ने हाल में 50 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। इस लिहाज से उसका मूल्यांकन 2.1 अरब डॉलर बैठता है। कंपनी ने शुक्रवार को कहा कि निहित विकल्पों वाले 200 मौजूदा और पूर्व कर्मचारी इस प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र होंगे। शेयरचैट ने मौजूदा वेस्टिंग शेड्यूल को भी संशोधित किया है। इसमें कहा गया है कि नई निहित नीति सभी योग्य कर्मचारियों को पहले वर्ष में 25 प्रतिशत इसॉप और उसके बाद हर तिमाही में 8.25 प्रतिशत का निवेश करने की अनुमति देती है। शेयरचैट के एक व रिष्ठ अ धिकारी ने कहा कि हमने जो वृद्धि हासिल की है, वह हमारे लोगों प्रतिबद्धता के बिना हासिल नहीं हो सकती थी। उन्होंने कहा कि इसॉप की वापस खरीद कर्मचारियों को कुछ वापस लौटाने का प्रयास है। इस पुनर्खरीद कार्यक्रम में मोहल्ला टेक एकमात्र खरीदार होगी। सभी पात्र कर्मचारी अपने 100 प्रतिशत निहित इसॉप मौजूदा शेयर मूल्य के भाव पर बेच सकेंगे।

अडाणी समूह के डीमैट अकाउंट ब्लॉक होने की खबर बकवास: सीएफओ

नई दिल्ली। पिछले दिनों कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ने कहा था कि नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा तीन फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स फंड का डीमैट अकाउंट ब्लॉक किया गया है। इससे अडाणी समूह की कंपनियों के शेयरों में उतार-चढ़ाव आया लेकिन अडाणी समूह ने साफ कहा है कि ये खबर बकवास है और बाजार में अफवाह फैलाई गई है। इस संदर्भ में अडाणी ग्रुप के सीएफओ जुगेशिंदर सिंह ने कहा कि अडाणी समूह के कुछ एफपीआई के फ्रीज होने की जो समाचार चली, वह सही नहीं है। हम किसी एक निवेशक से विशेष स्पष्टीकरण नहीं मांगते हैं, हम नियामकों से स्पष्टीकरण चाहते हैं। हमने स्पष्टीकरण मांगा है, नियामक ने स्पष्ट कहा, ये फंड फ्रीज नहीं हैं। वे सक्रिय हैं और वे सक्रिय रूप से व्यापार कर रहे हैं। यह एक स्वयंसिद्ध तथ्य है। स्पष्ट रूप से झूठी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए यह एक केंद्रित दुर्भावनापूर्ण प्रयास हो रहा है और बस इतना ही है। इसका मतलब है कि हमें उन उपायों की तलाश करनी पड़ सकती है जो हमारे लिए उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि यह हमारे अल्पसंख्यक निवेशकों को नुकसान पहुंचाता है, जिसकी हम जांच करेंगे।

चालू वित्त वर्ष में चीनी उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़कर 307 लाख टन रहा

- देश से अब तक चीनी निर्यात के 58 लाख टन के निर्यात अनुबंध हुए

नई दिल्ली।

देश में गन्ने का उत्पादन बढ़ने से विपणन वर्ष 2020-21 में 15 जून तक चीनी उत्पादन 13 प्रतिशत बढ़कर 306.65 लाख टन पर पहुंच गया है। उद्योग के आंकड़ों में यह जानकारी दी गई है। चीनी विपणन वर्ष अक्टूबर से सितंबर तक होता है। इसके साथ ही देश से अब तक चीनी निर्यात के 58 लाख टन के निर्यात अनुबंध किए जा चुके हैं। जिसमें से 45 लाख टन से अधिक चीनी का निर्यात किया जा चुका है। भारतीय चीनी मिल संघ (इस्मा) ने कहा कि देश भर की चीनी मिलों ने एक अक्टूबर 2020 और 15 जून 2021 के बीच 306.65 लाख टन चीनी का उत्पादन किया है। यह पिछले साल की समान अवधि में उत्पादित 271.11 लाख टन से 35.54 लाख टन अधिक है। मौजूदा समय में देश में केवल पांच चीनी मिलें चल रही हैं। उत्तर प्रदेश में चीनी उत्पादन वर्ष 2020-21 में 15 जून तक 110.61 लाख टन का हुआ है, जबकि पिछले वर्ष इसी अवधि में उत्पादन 126.30 लाख टन रहा था। समीक्षाधीन अवधि के दौरान महाराष्ट्र में चीनी उत्पादन पहले के 61.69 लाख टन से बढ़कर 106.28 लाख टन हो गया। जबकि कर्नाटक में उत्पादन पहले के 33.80 लाख टन से बढ़कर 41.67 लाख टन हो गया। इस्मा ने कहा कि बंदरगाह की सूचना और बाजार रिपोर्ट के अनुसार चीनी मिलों ने वर्ष 2020-21 के लिए 60 लाख टन चीनी निर्यात के सरकारी कोटे के मुकाबले अब तक 58 लाख टन चीनी के निर्यात का अनुबंध किया है। इसमें से करीब 45.74 लाख टन चीनी का निर्यात किया जा चुका है। यह भी बताया गया है कि जून 2021 में निर्यात की जाने वाली 5-6 लाख टन चीनी पाइपलाइन में है। इनके अलावा, चीनी उद्योग ने विपणन वर्ष 2019-20 के निर्यात कोटा के मुकाबले अक्टूबर-दिसंबर 2020 तिमाही में 4.49 लाख टन चीनी का निर्यात किया था। इस्मा ने कहा कि चीनी की मांग विपणन वर्ष 2020-21 में 260 लाख टन को पार कर सकती है, जबकि पिछले वर्ष यह मांग 253 लाख टन रही थी। उद्योग संगठन ने 70 लाख टन चीनी निर्यात का अनुमान लगाया है। पिछले सत्र की तुलना में इस साल सितंबर आ खिरी तक 8-10 लाख टन की अधिक घरेलू बिक्री के अलावा, चालू वर्ष में चीनी का निर्यात लगभग 70 लाख टन होने की उम्मीद है, जो उद्योग को विश्वास दिलाता है कि सितंबर 2021 में चीनी का 'शेष स्टॉक' पिछले सत्र के शेष स्टॉक के मुकाबले 20-25 लाख टन कम रहेगा।

पैन को आधार से करें लिंक नहीं तो कटेगा ज्यादा टीडीएस

नई दिल्ली।

आयकर नियमों के तहत सभी को अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक करना अनिवार्य है। इसके लिए आयकर विभाग ने 30 जून की डेडलाइन रखी है। यदि आप 30 जून तक पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करते हैं तो आयकर नियम-1962 के नियम 114एएए(3) के तहत आपका पैन कार्ड इनवैलिड हो जाएगा। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 206एए(6) के तहत टीडीएस डिडक्शन के लिए दिया गया आपका पैन कार्ड यदि वैलिड या ऑपरेटिव नहीं होता है तो माना जाता है कि व्यक्ति ने टीडीएस काटने वाले के पास पैन डिटेल जमा नहीं की है और फिर इस स्थिति में धारा 206एए(6) के प्रावधान लागू होते हैं और ऐसे में आपका टीडीएस 20 प्र तिशत कटता है। हालांकि टीडीएस की 20 प्र तिशत दर केवल फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज या डिविडेंट से होने वाली आय पर ही लगती है. या उन बातों के लिए जहां पर टीडीएस का नियम लागू हैं, जहां ऐसा नहीं है वहां ये नियम लागू नहीं होगा। आयकर कानून के हिसाब से कर भरना करदाता की जिम्मेदारी है। ऐसे में आधार और पैन को लिंक करने के बाद आपको बैंक, ब्याज से आय के लिए पोस्ट ऑफिस, लाभांश के लिए कंपनियों, म्यूचुअल फंड कंपनियों वगैरह को इसकी जानकारी देनी होगी ताकि ज्यादा टीडीएस ना कटे। पैन और आधार को लिंक करना अनिवार्य है। इससे आपके बैंकिंग लेनदेन सरल बने रहेंगे, ज्यादा टीडीएस नहीं कटेगा, डीमैट एकाउंट पर ट्रेडिंग भी सामान्य तरीके से हो सकेगी।

गिरावट से उबरा शेयर बाजार, हरे निशान पर बंद हुआ सेंसेक्स

मुंबई:

लगभग पूरे दिन गिरावट में रहने के बाद आखिरी समय में निजी बैंकों तथा वित्तीय कंपनियों के शेयरों में हुई लिवाली से बीएसई का सेंसेक्स और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी आज हरे निशान में बंद हुए। पिछले दो कारोबारी सत्रों में लाल निशान में बंद होने वाला बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स कारोबार की समाप्ति पर 21.12 अंक यानी 0.04 प्रतिशत की बढ़त के साथ 52,344.45 अंक पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 33.55 अंक यानी 0.21 प्रतिशत चढ़कर 15,724.95 अंक पर रहा। शेयर बाजार में आज का दिन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। सुबह करीब 245 अंक की तेजी में खुलने वाला सेंसेक्स दोपहर से पहले एक समय सेंसेक्स 722 अंक लुढ़क गया था। कारोबार की समाप्ति तक निजी बैंकों और वित्तीय कंपनियों के साथ रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में लौटी लिवाली से यह हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहा। बिजली, धातु, तेल एवं गैस, यूटिलिटीज, बुनियादी वस्तुएं और रियलिटी जैसे समूहों के सूचकांकों में बड़ी गिरावट देखी गई। दूरसंचार समूह का सूचकांक करीब डेढ़ प्रतिशत चढ़ गया। मझौली और छोटी कंपनियों में बिकवाली का जोर रहा। बीएसई का मिडकैप 0.70 फीसदी लुढ़ककर 22,238.21 अंक पर बंद हुआ। छोटी कंपनियों का सूचकांक स्मॉलकैप भी 0.89 प्रतिशत टूटकर 24,648.83 अंक पर रहा। सेंसेक्स की 30 में से 18 कंपनियों के शेयर लाल निशान में और शेष 12 के हरे निशान में रहे। ओएनजीसी में सबसे अधिक 3.72 प्रतिशत की गिरावट रही। एनटीपीसी का शेयर 3.16 फीसदी, पावर ग्रिड का 2.80 फीसदी, महिंद्रा एंड महिंद्रा का 2.56 फीसदी और नेस्ले इंडिया का 2.08 प्रतिशत लुढ़क गया। भारतीय स्टेट बैंक का शेयर 1.76 फीसदी और एचसीएल टेक्नोलॉजीज का 1.13 प्रतिशत नीचे बंद हुआ। हिंदुस्तान यूनिलिवर का शेयर 2.64 प्रतिशत, बजाज ऑटो का 2.61 प्रतिशत, भारतीय एयरटेल का 1.93 प्रतिशत, बजाज फिनसर्व का 1.51 प्रतिशत और इंडसइंड बैंक का 1.08 प्रतिशत की बढ़त में बंद हुआ। विदेशों में मिश्रित रुख रहा। एशिया में जापान का निक्केई 0.19 प्रतिशत और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.01 प्रतिशत की गिरावट में रहा। वहीं, हांगकांग का हैंगसेंग 0.85 प्रतिशत और दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.09 प्रतिशत मजबूत हुआ। यूरोप में शुरुआती कारोबार में ब्रिटेन का एफटीएसई 0.98 प्रतिशत और जर्मनी का डैक्स 0.70 प्रतिशत टूट गया।

हवाई अड्डा खरीद टालेंगे अडानी!

नई दिल्ली:

अडानी समूह ने तीन हवाई अड्डों- जयपुर, गुवाहाटी और तिरुवनंतपुरम के अधिग्रहण को दिसंबर तक टाल दिया है। समूह ने इसके पीछे तर्क दिया है कि महामारी की दूसरी लहर के कारण व्यवधान आने से हवाई अड्डों का परिचालन अपने हाथों में लेने में अक्षम है। मामले के जानकार सूत्रों ने कहा कि अडानी समूह ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) को पत्र लिखकर फोर्स मेज्योर प्रावधान के तहत हवाई अड्डों के अधिग्रहण को छह महीने टालने की मांग की है। तीनों हवाई अड्डों के लिए बाध्यकारी रियायत समझौते की शर्तों पर 19 जनवरी को हस्ताक्षर किए गए थे और अडानी समूह को 180 दिन के अंदर इन हवाई अड्डों के प्रबंधन तथा परिचालन का नियंत्रण अपने हाथों में लेना था। एएआई बोर्ड जून के अंत में होने वाली बैठक में इस मसले पर निर्णय करेगा। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, कंपनी ने विमानन क्षेत्र के मौजूदा अड़चनों को देखते हुए अधिग्रहण में अक्षमता का हवाला देकर फोर्स मेज्योर लागू करने की मांग की है। समझौते में शामिल इस प्रावधान के तहत दोनों पक्षों के नियंत्रण से परे असाधारण स्थिति में अधिग्रहण में देरी करने की अनुमति दी जा सकती है। फरवरी 2020 में कंपनी ने अहमदाबाद, लखनऊ और मंगलूरु हवाई अड्डे के अधिग्रहण में देरी के लिए भी इसी तरह फोर्स मेज्योर प्रावधान का उपयोग किया था, जिसके तहत एएआई ने अधिग्रहण की समयसीमा छह महीने बढ़ा दी थी। बाद में समूह ने नवंबर में तीनों हवाई अड्डों का अधिग्रहण किया था। 2019 में अडानी समूह ने आक्रामक बोली के जरिए एएआई के स्वामित्व वाले छह हवाई अड्डों को उन्नत बनाने और उनका परिचालन का अधिकार हासिल किया था। उदाहरण के लिए जीएमआर समूह ने अहमदाबाद और जयपुर हवाई अड्डे के लिए प्रति यात्री क्रमश- 85 रुपए और 69 रुपए की बोली लगाई थी हजबकि अडानी ने इसके लिए क्रमश- 177 रुपए और 174 रुपए प्रति यात्री की बोली लगाई थी। कंपनी की योजना से वाकिफ सूत्रों का कहना है कि समूह हवाई अड्डों का अधिग्रहण करने के लिए तैयार था लेकिन महामारी की दूसरी लहर की वजह से प्रबंधन नियंत्रण में बदलाव से पहले परिसंपत्तियों के सत्यापन तथा वित्तीय क्लोजर में देरी की वजह से पूरी प्रक्रिया में देरी हुई। दिल्ली और मुंबई हवाई अड्डों के प्रबंधन में बदलाव की प्रक्रिया में शामिल रहे उद्योग एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि प्रबंधन और परिचालन नियंत्रण में बदलाव में परिसंपत्तियों के सत्यापन सहित कई चीजें शामिल होती हैं। उन्होंने कहा, मान लीजिए समझौते में कहा गया है कि हवाई अड्डे पर 50 एक्स-रे मशीनें हैं। ऐसे में अडानी को प्रबंधन अपने हाथ में लेने से पहले उसकी पुष्टि करनी होगी और यह भी देखना होगा कि उसकी स्थिति कैसी है। इसी तरह अन्य उपकरणों का भी भौतिक सत्यापन करना होता है। यह जटिल प्रक्रिया है जिसमें काफी श्रमबल लगता है। हालांकि कंपनी मुंबई इंटरनैशनल एयरपोर्ट (मायल) का प्रबंधन अधिग्रहण में ज्यादा सक्रिय रही थी। कंपनी ने पिछले साल अगस्त में जीवीके समूह से इस हवाई अड्डे के परिचालन का नियंत्रण हासिल किया था। गौतम अडानी के बेटे करण अडानी, जो अडानी पोर्ट्स एसईजेड के मुख्य कार्याधिकारी हैं और अडानी कैपिटल के मुख्य कार्याधिकारी गौरव गुप्ता को कंपनी के निदेशक मंडल में शामिल किया गया है।

सरकार ने खाद्य तेलों का आयात शुल्क घटाया, कीमतों में आएगी कमी

मुंबई ।

सरकार ने पाम तेल सहित खाद्य तेलों के आयात शुल्क में 112 डॉलर प्रति टन तक की कटौती की है, जिससे खाद्य तेल की घरेलू कीमतों में गिरावट आ सकती है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना जारी कर कच्चे पाम तेल के आयात पर शुल्क मूल्य में 86 डॉलर प्रति टन और आरबीडी (रिफाइंड, ब्लीच्ड एंड डियोडराइज्ड) एवं कच्चे पामोलिन के आयात पर शुल्क मूल्य में 112 डॉलर प्रति टन की कटौती की गई है। कच्चे सोयाबीन तेल के आधार आयात मूल्य में भी 37 डॉलर प्रति टन की कमी की गई है। खाद्य तेल के आयात शुल्क मूल्य में बदलाव गुरुवार 17 जून से प्रभाव में आएगा। कर विशेषज्ञों ने कहा कि शुल्क मूल्य में कटौती से घरेलू बाजार में खाद्य तेल की कीमतें कम हो सकती हैं क्योंकि इससे आधार आयात मूल्य पर देय सीमा शुल्क कम हो जाता है। विशेषज्ञों ने कहा कि खाद्य तेल तिलहन की घरेलू खपत और मांग के बीच देश में बड़ा फासला है जिसकी वजह से इनका बड़ी मात्रा में आयात किया जाता है। पिछले कुछ माह के दौरान इनके खुदरा मूल्य में तेजी आई है। उन्होंने कहा कि आधारभूत आयात मूल्य में होने वाले इस बदलाव का खुदरा दाम पर असर पड़ सकता है बशर्ते कि विनिर्माता, वितरकों और खुदरा विक्रेताओं सहित पूरी आपूर्ति श्रृंखला से इस कटौती का लाभ उपभोक्ता तक पहुंचाया जाए।

पीएफसी कंसल्टिंग ने यूपी में ट्रांसमिशन परियोजनाओं के लिए एसपीवी की स्थापना की

नई दिल्ली।

बिजली क्षेत्र के ऋणदाता पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में एक ट्रांसमिशन योजना विकसित करने के लिए एक विशेष उद्देश्य वाहन को शामिल किया है। स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में, पीएफसी ने कहा कि उसकी परामर्श सहायक कंपनी ने एक एसपीवी और मोहनलालगंज ट्रांसमिशन लिमिटेड को शामिल किया है यह एसपीवी 400,220,132 केवी जीआईएस सबस्टेशन, मोहनलालगंज (लखनऊ) से जुड़ी 400 केवी लाइनों के साथ, और 765 केवी जीआईएस सबस्टेशन रामपुर और 400 केवी एलआईएलओ (मोनोपोल पर क्वाड मूस) पर अन्य 765 केवी और 400 केवी एलआईएलओ लाइनों के निर्माण से जुड़ी ट्रांसमिशन योजना 400 केवी जीआईएस सबस्टेशन सेक्टर 123 नोएडा में लागू करेगा। पीएफसी एसपीवी मार्ग के तहत बिजली परियोजनाओं को लागू करता है और यह एक ऐसा उपाय है जहां ऋणदाता की सहायक वास्तव में एक पारेषण परियोजना को लागू करेगी।

आंगनवाड़ी, मध्याह्न भोजन के लिये खाने की आपूर्ति पर जीएसटी से पूरी तरह छूट है: सीबीआईसी

नयी दिल्ली,

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने कहा है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत स्कूलों और आंगनवाड़ी के लिये खाने के सामान की आपूर्ति पर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से छूट है। जीएसटी परिषद की 28 मई को हुई 43वीं बैठक में किये गये फैसलों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए सीबीआईसी ने कहा कि उससे जीएसटी लागू होने के बारे में जानकारी मांगी गयी है। उसमें पूछा गया है कि मध्याह्न भोजन योजना के तहत अगर स्कूलों में सरकारी अनुदान और/या कंपनी दान के जरिये वित्त पोषित खाद्य पदार्थ की आपूर्ति की जाती है तो क्या वह जीएसटी के दायरे में आएगा। वस्तु एवं सेवा कर के तहत, किसी शैक्षणिक संस्थान को प्रदान की जाने वाली मध्याह्न भोजन सहित कोई भी खानपान सेवा पूरी तरह से शुल्क मुक्त है। सीबीआईसी ने कहा कि इसमें प्री-स्कूल सहित किसी भी स्कूल को खाना परोसना शामिल होगा। इसके अलावा, एक आंगनवाड़ी जो अन्य बातों के अलावा स्कूली शिक्षा से पहले की गैर-औपचारिक शिक्षा प्रदान करती है और इसलिए आंगनवाड़ी शैक्षणिक संस्था (प्री-स्कूल के रूप में) की परिभाषा के अंतर्गत आती है। ''...यह स्पष्ट किया जाता है कि किसी शैक्षणिक संस्थान को भोजन उपलब्ध (मध्याह्न भोजन सहित खानपान) कराकर प्रदान की जाने वाली सेवाएं जीएसटी से मुक्त है, भले ही उसका वित्त पोषण सरकारी अनुदान या कॉर्पोरेट दान से हुआ हो।'' सीबीआईसी ने 17 जून के कहा, ''जीएसटी अधिसूचना में परिभाषित शैक्षणिक संस्थानों में आंगनवाड़ी शामिल है। अतः चाहे वह सरकार द्वारा प्रायोजित हो या निगमों से दान के माध्यम से, आंगनबाड़ी को भोजन परोसना भी उक्त छूट के दायरे में आएगा।'' ईवाई कर भागीदार अभिषेक जैन के अनुसार सरकार ने स्पष्ट किया है कि शैक्षणिक संस्थानों को प्रदान की जाने वाली खानपान सेवाओं पर जीएसटी छूट का दायरा व्यापक होगा। संबंधित पक्ष इसकी सराहना करेंगे। उन्होंने कहा, ''इस स्पष्टीकरण से भोजन उपलब्ध कराने में शामिल शिक्षण संस्थानों को जीएसटी की वजह से अपनी लागत को कम करने में मदद मिलेगी। इससे ऐसे संस्थानों के कोष की बचत होगी।'' सीबीआईसी ने केंद्रीय और राज्य बोर्ड (जैसे राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड) द्वारा दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं पर जीएसटी को लेकर अलग से स्पष्टीकरण दिया है।

अडानी ने चार दिन में गंवाए 98 हजार करोड़

नई दिल्ली।

अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में गिरावट का सिलसिला सोमवार से शुक्रवार तक लगातार चार दिन जारी रहा। इससे अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी की नेटवर्थ में पिछले चार दिन में 13.2 अरब डॉलर यानी करीब 97852 करोड़ रुपए की गिरावट आई है। उनकी नेटवर्थ अब 65.5 अरब डॉलर रह गई है और वह एशिया में दूसरे से तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं। अडानी की नेटवर्थ जितनी तेजी से बढ़ी थी, उससे ज्यादा तेजी से गिर रही है। इस हफ्ते दुनिया के किसी दूसरे अरबपति के मुकाबले अडानी के नेटवर्थ में सबसे अधिक गिरावट आई है। कुछ समय पहले तक वह एशिया के सबसे अमीर शख्स मुकेश अंबानी के काफी करीब पहुंच गए थे। तब लग रहा था कि वह रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन से आगे निकल जाएंगे लेकिन एक रिपोर्ट ने उनके मंसूबों पर पानी फेर दिया। एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि एनएसडीएल ने तीन विदेशी फंड्स के खाते फ्रीज कर दिए हैं। इनके पास अडानी ग्रुप की 4 कंपनियों के 43,500 करोड़ रुपये के शेयर हैं। हालांकि अडानी ग्रुप ने इसका खंडन किया है, लेकिन इस खुलासे के बाद से अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है। शुक्रवार को भी उनकी 6 कंपनियों में से 3 के शेयरों में करीब 5 फीसदी की गिरावट के बाद फिर से लोअर सर्किट लग गया है। ग्रुप की सबसे मूल्यवान कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयरों में इस हफ्ते 12.4 फीसदी गिरावट आई है।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

यूएफा ने यूरो 2020 टीमों से कहा- प्रायोजक कंपनियों की बोतलें नहीं हटाएं

जिनेवा । स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो द्वारा यूरोपीय चैम्पियनशिप में बोतल हटाने के चलन पर प्रतिक्रिया देते हुए यूएफा ने गुरूवार को 24 टीमों के खिलाड़ियों से कहा कि वे प्रेस कांफ्रेंस मंचों पर रणनीति के तहत रखी गई प्रायोजक कंपनियों की ड्रिंक्स बोतलों को हटाना बंद कर दें। रोनाल्डो, पॉल पोग्बा और मैनुअल लोकाटेली सभी इस हफ्ते जब प्रेस कांफ्रेंस के दौरान अपनी सीट पर बैठे तो उन्होंने कैमरे के सामने आ रही प्रायोजकों की सभी बोतलों को हटा दिया। यूरो 2020 के टूर्नामेंट निदेशक मार्टिन कालेन ने कहा कि यूएफा (यूरोपीय फुटबॉल संघों के संघ) ने इस संबंध में टीमों को सूचित किया है। कालेन ने कहा कि यह महत्वपूर्ण है क्योंकि टूर्नामेंट और यूरोपीय फुटबॉल के लिए प्रायोजकों के राजस्व महत्वपूर्ण हैं। पोग्बा मुस्लिम हैं और वह एल्कोहल नहीं पीते, उन्होंने यूरो 2020 की अधिकारिक बीयर प्रायोजन हेनेकेन की हरी बोतल पर आपत्ति जताई थी। कालेन ने कहा कि टूर्नामेंट के नियमों में यूएफा के प्रायोजकों को किए गए वादों का अनुपालन करना जरूरी है, हालांकि धर्म के कारण आपत्ति रखने वाले खिलाड़ियों के लिए वहां बोतल की जरूरत नहीं है। रोनाल्डो ने सोमवार को मैच के पूर्व अनिवार्य प्रेस कांफ्रेंस में कोका कोला की दो बोतलों को हटाकर उनकी जगह एक पानी की बोतल रख दी जो भी एक ड्रिंक कंपनी के ब्रांड की थी। रोनाल्डो के ऐसा करने से कोका कोला के शेयरों में गिरावट दर्ज की गयी, लेकिन दोनों चीजों में संबंध का कोई सबूत नहीं है।

विंडीज क्रिकेट बोर्ड और बीसीसीआई के बीच टी20 लीग को लेकर हुई सहमति, नहीं होगा तारीखों का टकराव

नई दिल्ली ।

क्रिकेट वेस्ट इंडीज (सीडब्ल्यूआई) भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के आईपीएल के शेष सत्र को पूरा करने के लिए कैरेबियाई प्रीमियर लीग (सीपीएल) की तारीखों में बदलाव के आग्रह पर सहमत हो गया है। दोनों क्रिकेट बोर्ड के बीच हुए समझौते के तहत अब आईपीएल और सीपीएल दोनों टूर्नामेंट एक दूसरे से टकराए बिना आयोजित हो सकेंगे। सीपीएल के आयोजकों ने बीसीसीआई के आग्रह को स्वीकार करते हुए सीपीएल की तारीखों को आगे बढ़ा दिया है, ताकि 14 सितंबर के बाद उपलब्ध सीमित विंडो में आईपीएल को पूरा किया जा सके, तब भारतीय टीम इंग्लैंड दौरे से मुक्त हो जाएगी। आयोजक जल्द ही सीपीएल का संशोधित कार्यक्रम जारी कर सकते हैं। बीसीसीआई के सचिव जय शाह की सीपीएल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीओओ) पीट रसेल से मुलाकात के बाद बीसीसीआई और सीपीएल अधिकारियों की ओर से नई व्यवस्था पर सहमति व्यक्त जताई गई है। बीसीसीआई सचिव ने क्रिकेट वेस्ट इंडीज में अपने समकक्षों से भी बात की है, जिसके बाद कैरेबियाई क्रिकेट अधिकारियों ने सीपीएल कार्यक्रम में बदलाव करने पर सहमति जताई है। क्रिकेट वेस्ट इंडीज के अध्यक्ष रिकी स्केरिट ने सीपीएल शेड्यूल में प्रस्तावित बदलावों की पुष्टि करते हुए कहा कि क्रिकेट वेस्ट इंडीज बिना किसी परस्पर विरोधी ओवरलैप के सीपीएल से आईपीएल में एक सुचारु परिवर्तन की सुविधा में मदद करने के लिए अपनी पूरी कोशिश कर रहा है। समझा जाता है कि सीपीएल अब 25 अगस्त से 15 सितंबर तक आयोजित होगा, जिससे बीच में ही स्थगित आईपीएल का शेष सत्र 18 या 19 सितंबर के आसपास फिर से शुरू हो सकेगा। मूल रूप से सीपीएल 28 अगस्त से 19 सितंबर तक होना था। सीपीएल ने 27 अप्रैल को कहा था कि सेंट किट्स एंड नेविस में 28 अगस्त से टूर्नामेंट शुरू होगा और कुल 33 मैच खेले जाएंगे। टूर्नामेंट 26 अगस्त को भी शुरू हो सकता है, ताकि पाकिस्तान के खिलाफ वेस्ट इंडीज के दूसरे टेस्ट और सीपीएल की शुरुआत के बीच 24 घंटे से अधिक का अंतर हो। टेस्ट मैच 24 अगस्त को समाप्त होना है।

बारिश के कारण पहले सत्र में नहीं हो पाया खेल

लंदन।

साउथैंप्टन में लगातार बारिश के कारण भारत और न्यूजीलैंड के बीच पहले विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप (डब्ल्यूटीसी) फाइनल का अहम मुकाबला अब तक शुरु नहीं हो पाया है। बारिश के कारण दिन के पहले सत्र का खेल नहीं हो पाया। मैच बीसीसीआई ने अपने एक ट्वीट में कहा कि बारिश के चलते टॉस भी देरी से होगा और खेल कब शुरू होगा इसका फैसला मैच रैफरी बारिश रुकने के बाद पिच और मैदान का मुआयना करने के बाद करेंगे। वहीं माना जा रहा है कि पहले दिन का खेल शायद ही हो पाये। इसका कारण यह है कि मौसम विभाग ने साउथैंप्टन में

येलो अलर्ट जारी किया है जिसके अनुसार आज पूरे दिन वहां बारिश हो सकती है। साउथैंप्टन में कल शाम से ही बारिश शुरू हो गई थी। वहीं दूसरे दिन भी ऐसा ही मौसम रहने की आशंका जताई जा रही है. मौसम विभाग के अनुसार दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक वहां बारिश होगी। इसके बाद बरसात रुकेगी पर बादल छाए रहेंगे। फिर 2 बजे से एक बार फिर बादल बरसेंगे और ये सिलसिला अगले दो घंटे तक जारी रहने की आशंका है।

शाम 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक बारिश ना होने की बात कही गई है लेकिन इसके बाद फिर बारिश हो सकती है।

मंत्रालय ने राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आवेदन जमा करने की समय सीमा बढ़ायी

नयी दिल्ली, खेल मंत्रालय ने इस साल के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन जमा करने की समय सीमा शुक्रवार को एक सप्ताह बढ़ा दी, जिससे यह ऑनलाइन प्रक्रिया 28 जून तक जारी रहेगी।इससे पहले नामांकन और आवेदन जमा करने की आखिरी तारीख 21 जून तय की गयी थी। भारत सरकार के अवर सचिव सुदर्शन गरलापति द्वारा जारी एक परिपत्र के मुताबिक, '' आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 21 जून, 2021 से बढ़ाकर 28 जून, 2021 करने का निर्णय किया गया है।'' खेल मंत्रालय ने 20 मई को राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन आमंत्रित किए थे, जिससे पात्र एथलीटों, कोचों, विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को स्व-नामांकन करने और कोविड-19 महामारी के कारण लगातार दूसरे वर्ष इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की मांग की गयी थी। इससे पहले 2019 तक आवेदकों को आवेदन करने में सक्षम होने के लिए सिफारिशों की आवश्यकता पड़ती थी। पिछले साल हालांकि इस शर्त को हटा दिया गया था क्योंकि लॉकडाउन के कारण लोगों का कहीं आना-जाना संभव नहीं था। पिछले साल ऑनलाइन समारोह में 74 प्राप्तकर्ताओं ने पुरस्कार लिये थे। इस दौरान पुरस्कार राशि में बड़ी बढ़ोतरी करते हुए खेल रत्न पुरस्कार विजेताओं को 25 लाख रुपये, अर्जुन पुरस्कार विजेताओं को 15 लाख रुपये, द्रोणाचार्य (जीवनपर्यंत) 15 लाख रुपये और ध्यानचंद पुरस्कार विजेताओं को 10 लाख रुपये पुरस्कार राशि के तौर पर दिये गये थे।इसके साथ ही अभूतपूर्व कदम के तहत पिछले साल क्रिकेटर रोहित शर्मा, महिला हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल, पहलवान विनेश फोगाट, पैरालिंपियन मरियप्पन थंगावेलु और टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा को संयुक्त रूप से खेल रत्न से सम्मानित किया गया था।

इंग्लैंड बनाम भारत महिला टेस्ट

शैफाली वर्मा ने राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड की बराबरी की

स्पोर्ट्स डेस्क।

शैफाली वर्मा ने ब्रिस्टल में अपने डेब्यू टेस्ट मैच में इंग्लैंड के खिलाफ 96 रनों की शानदार पारी के दौरान कई रिकॉर्ड बनाए। वह पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनीं जिन्होंने डेब्यू टेस्ट में 90 से ज्यादा स्कोर बनाए। इसी के साथ ही उन्होंने द वॉल कहे जाने वाले राहुल द्रविड़ के रिकॉर्ड की भी बराबरी कर ली है। भारत के पूर्व कप्तान द्रविड़ ने भी डेब्यू टेस्ट में 90+ स्कोर बनाए थे। यहां दिलचस्प बात यह भी है कि राहुल द्रविड़ का डेब्यू भी इंग्लैंड के खिलाफ ही हुआ था।क्रिस लुईस की गेंद पर जैक रसेल के हाथों आउट होने से पहले उन्होंने 95 रन बनाए। उसी मैच में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष और भारत के पूर्व कप्तान सौरव गांगुली ने भी टेस्ट क्रिकेट में पदार्पण किया था 131 रन बनाए थे। गांगुली के रिकॉर्ड को हाल ही में न्यूजीलैंड के डेविन कॉन्वे ने तोड़ा है। द्रविड़ के रिकॉर्ड की बराबरी के अलावा शैफाली अपने डेब्यू टेस्ट में छक्का लगाने वाली पहली भारतीय महिला भी बनीं। विशेष रूप से शैफाली ने टेस्ट पारी में एक महिला द्वारा सर्वाधिक छक्के लगाने के रिकॉर्ड की भी बराबरी की। उसने ब्रिस्टल में 2 बड़े छक्के लगाते हुए एलिसा हीली और लॉरेन विनफील्ड-हिल के संयुक्त रिकॉर्ड की बराबरी की। वहीं इस दौरान शैफाली वर्मा ने स्मृति मंधाना के साथ मिलकर पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी भी की। शैफाली और मंधाना ने पहले विकेट के लिए 167 रन जोड़े और 1984 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में संध्या अग्रवाल और गरजी बनर्जी के 153 के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। यह घर से दूर महिला टेस्ट क्रिकेट में दूसरी सबसे बड़ी साझेदारी भी थी।

संक्षिप्त समाचार

पृथकवास में टीम में बनी एकजुटता से भारत को अंतिम क्वालीफायर में लाभ मिल सकता है : दीपिका

कोलकाता, भारत की शीर्ष तीरंदाज दीपिका कुमारी का मानना है कि पेरिस में 10 दिन के पृथकवास के दौरान टीम के बीच आपसी समझ मजबूत हुई है जिसका तोक्यो ओलंपिक के लिये रविवार से शुरू होने वाले अंतिम क्वालीफायर में मदद मिलेगी। विश्व में तीसरे नंबर की तीरंदाज दीपिका पहले ही व्यक्तिगत रिकर्व वर्ग में ओलंपिक के लिये क्वालीफाई कर चुकी है लेकिन इस बार उनके सामने अलग तरह की चुनौती है। सबसे सीनियर तीरंदाज होने के कारण उन्हें अपनी टीम से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करवाना होगा। टीम में कोमालिका बारी और अंकिता भक्त जैसी युवा खिलाड़ी शामिल हैं।दीपिका ने अंतिम क्वालीफायर से पूर्व पेरिस से पीटीआई से कहा, ''आम तौर पर मैं अलग रहती हूं और जूनियर के साथ घुलने मिलने के लिये समय निकालती हूं लेकिन विची में पृथकवास के दौरान हमने अभ्यास के बाद कई घंटे साथ में बिताये। '' उन्होंने कहा, ''टीम गेम में पारदर्शिता होनी चाहिए और मुझे लगता है कि इससे (पृथकवास) हमें काफी मदद मिल रही है। मैं टीम के बीच तालमेल से खुश हूं। अब हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझते हैं। '' दीपिका ने कहा, ''टीम की सबसे सीनियर सदस्य होने के कारण मेरी प्राथमिकता हर समय आत्मविश्वास में रहना है ताकि इससे मेरी साथियों का भी हौसला बढ़े। अच्छा प्रदर्शन करना है और करवाना भी है। यह मेरा काम है। ''

नडाल और ओसाका ने विम्बलडन से वापस लिया नाम, ओलंपिक खेलेगी ओसाका

वाशिंगटन । राफेल नडाल और नाओमी ओसाका ने विम्बलडन से नाम वापस ले लिया है और कोरोना महामारी के कारण पिछले साल रद्द हुए इस सबसे पुराने टेनिस ग्रैंडस्लैम की चमक इससे कुछ फीकी हो गई है। दो बार के चैम्पियन नडाल ने सोशल मीडिया पर सिलसिलेवार पोस्ट करके यह जानकारी दी कि वह विम्बलडन और तोक्यो ओलंपिक नहीं खेलेंगे ताकि अपने शरीर को जरूरी आराम दे सकें। इस 35 वर्षीय खिलाड़ी ने कहा, 'मेरा लक्ष्य अपने करियर को विस्तार देना है और वह करना है जिससे मुझे खुशी मिले।' वहीं ओसाका के एजेंट स्टुअर्ट डुगुइड ने कहा कि चार बार की ग्रैंडस्लैम चैम्पियन ओसाका विम्बलडन नहीं खेलेंगी और तोक्यो ओलंपिक में भाग लेंगी। उन्होंने लिखा, 'वह परिवार और दोस्तों के साथ समय बिता रही है। वह ओलंपिक की तैयारी कर रही है और अपने देश में खेलने को लेकर रोमांचित है।' ओसाका का जन्म जापान में हुआ था और उनके पिता हैती से जबकि मां जापानी है। जब वह तीन वर्ष की थी, तभी परिवार अमेरिका आकर बस गई थी। दुनिया की दूसरे नंबर की खिलाड़ी ओसाका ने इस साल ऑस्ट्रेलियाई ओपन जीता लेकिन विवादों के बीच फ्रेंच ओपन से नाम वापस ले लिया। उन्हें मीडिया से अनिवार्य बातचीत के नियम पर ऐतराज था और पहले दौर की जीत के बाद उन्होंने मीडिया से बात नहीं की।

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए विंडीज टीम की घोषणा, गेब्रियल-ब्रावो की वापसी

सेंट लूसिया ।

वेस्ट इंडीज ने यहां आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे और अंतिम टेस्ट के लिए तेज गेंदबाज शैनन गेब्रियल और बाएं हाथ के बल्लेबाज डैरेन ब्रावो को टीम में वापस बुला लिया है। पहले टेस्ट में एक पारी और 63 रन से हारने के बाद क्रिकेट वेस्ट इंडीज के चयन पैनल ने दूसरे टेस्ट की पूर्व संध्या पर 13 सदस्यीय टीम चुनी। गुरुवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि पहले टेस्ट के दौरान सब्सीट्यूट के रूप में टीम में शामिल हुए नकरुमाह बोनर चोट के कारण चयन के लिए उपलब्ध नहीं थे। मुख्य चयनकर्ता रोजर हार्पर ने कहा था, 'शैनन गेब्रियल को पूरी तरह से फिट घोषित कर दिया गया है। पहले से टीम के तेज गेंदबाजी आक्रामण का नेतत्व करने के चलते वह 13 सदस्यीय टीम में लौट आए हैं। ब्रावो हमारे अनुभवी बल्लेबाज है और हमें बेहतरीन बल्लेबाजी का विकल्प देते हैं। टीम को अब उस स्टैंडर्ड के अनुरूप खेलना होगा जिस पर खेलने में सक्षम हैं। हमने पहले टेस्ट में अपनी क्षमता के करीब कहीं भी बल्लेबाजी नहीं की और हमें इस निर्णायक मैच में बल्ले से सुधार करना होगा। उल्लेखनीय है कि वेस्ट इंडीज की टीम पहले टेस्ट की दोनों पारियों में 97 और 162 रन पर ऑल आउट हो गई थी। रोस्टन चेज ने सर्वाधिक 62 रन बनाए थे, जबकि अन्य कोई बल्लेबाज दोनों पारियों में 20 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाया था।

वेस्टइंडीज की टीम ।

क्रेग ब्रैथवेट (कप्तान), जर्मेन ब्लैकवुड (उप कप्तान), डैरेन ब्रावो, रोस्टन चेज, रहकीम कॉर्नवाल, जोशुआ डा सिल्वा, शैनन गेब्रियल, जैसन होल्डर, शाई होप, काइल मेयर्स, कीरन पॉवेल, केमार रोच, जेडन सील्स।

स्पीड चैस शतरंज - भारत की हरिका नें रूस की अलेक्ज़ेंड्रा कोस्टेनियुक को हराया

नई दिल्ली (निकलेश जैन)

फीडे महिला स्पीड चैस शतरंज के प्री क्वाटर फ़ाइनल प्ले ऑफ मे भारत की ग्रांड मास्टर हरिका द्रोणावल्ली नें रूस की पूर्व विश्व चैम्पियन अलेक्ज़ेंड्रा कोस्टेनियुक को बेहद कड़े मुक़ाबले मे पराजित करते हुए क्वाटर फाइनल में प्रवेश कर लिया । दोनों के बीच कुल 27 मुक़ाबले खेले गए जिसमें अंत समय मे हारिका नें बेहद कड़े और रोमांचक मुक़ाबले मे 14.5-12.5 से जीत हासिल की । तीन अलग अलग फॉर्मेट मे खेले गए इन मुकाबलों मे कभी कोस्टेनियुक तो कभी हरिका आगे निकल रही थी । सबसे पहले 75 मिनट तक 5+1 मिनट प्रति खिलाड़ी के मुक़ाबले खेले गए जिसमें कुल 8 मुकाबलों के बाद कोस्टेनियुक 3 जीत और 5 ड्रॉ से 5.5 -2.5 से तीन अंक की मजबूत बढ़त बना चुकी थी और हरिका के लिए मैच मुश्किल होता जा रहा था पर इसके बाद 45 मिनट तक 3+1 मिनट के मुक़ाबले 7 मुक़ाबले खेले और यह हरिका के लिए वापसी का कारण बने हरिका नें सात मैच मे से 5 जीत 1 ड्रॉ और 1 हार से शानदार वापसी की और 8-7 से आगे हो गयी ।अब सबका ध्यान 25 मिनट तक 1+1 मिनट के मुकाबलों पर था और इस दौरान कुल 12 बुलेट मुक़ाबले खेले गए जिसमें 7.5- 4.5 से हरिका नें एक बार फिर से अच्छा खेल दिखाया और कुल 14.5- 12.5 से मैच जीतकर अंतिम 8 मे प्रवेश कर लिया ।

डोपिंग को लेकर रोमानिया ओलंपिक भारोत्तोलन से बाहर

लुसाने । पिछले डोपिंग मामलों के कारण रोमानिया के तोक्यो ओलंपिक की भारोत्तोलन स्पर्धा में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ ने यह फैसला किया। रोमानिया भारोत्तोलन महासंघ पर पांच डोपिंग मामलों के कारण एक साल का प्रतिबंध लगाया गया है। इसमें रोमानिया के चारों भारोत्तोलकों का 2012 ओलंपिक से बाहर होना शामिल है जिनके नमूनों की बाद में दोबारा हुई जांच में प्रतिबंधित पदार्थ पाए गए। इनमें से एक गैब्रियल सिनक्रेइयन ने 2016 रियो ओलंपिक में जीता पदक भी गंवा दिया। रोमानिया के अलावा मिस्र, मलेशिया और थाईलैंड भी तोक्यो ओलंपिक में भारोत्तोलन में भाग नहीं ले सकेंगे।

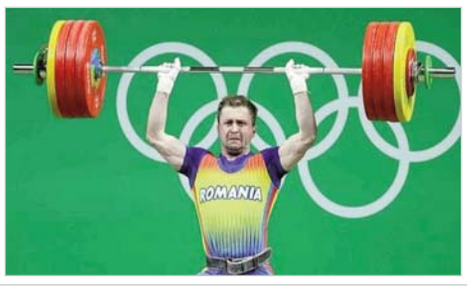

हॉकी इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक के लिए पुरुष टीम की घोषणा की

बेंगलुरू।

हॉकी इंडिया ने आगामी टोक्यो ओलंपिक खेलों 2020 में देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए बहुप्रतीक्षित 16 सदस्यीय पुरुष हॉकी टीम की शुक्रवार को घोषणा कर दी। टीम में 10 से अधिक खिलाड़ी ऐसे हैं, जो ओलंपिक में पदार्पण करेंगे। इस टीम में अनुभवी गोलकीपर पीआर श्रीजेश और मिडफील्डर मनप्रीत सिंह के साथ-साथ ओलंपिक खेल चुके अन्य खिलाड़ियों में हरमनप्रीत सिंह, रूपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार और मनदीप सिंह शामिल हैं।अनुभवी बीरेंद्र लाकड़ा को भी टोक्यो 2020 के लिए टीम का हिस्सा बनने का एक उपयुक्त अवसर मिला। इसके अलावा, अमित रोहिदास, हार्दिक सिंह, विवेक सागर प्रसाद, नीलकांत शर्मा, सुमित नवोदित फॉरवर्ड शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह और ललित कुमार उपाध्याय टीम में शामिल हो रहे हैं। टीम चयन पर बोलते हुए, मुख्य कोच ग्राहम रीड ने कहा, 16 खिलाड़ियों का अंतिम चयन करना आसान प्रक्रिया नहीं रही है क्योंकि खिलाड़ियों के इस समूह में बहुत सारी गुणवत्ता और महत्वाकांक्षा है। सभी एथलीटों का प्रदर्शन स्तर एक इष्टतम स्तर पर है और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि वे एक साथ अच्छा काम करते हैं। वे जानते हैं कि ओलंपिक में देश का प्रतिनिधित्व करने का क्या मतलब है। अब हम उसी तीव्रता के साथ प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और हमारा लक्ष्य टोक्यो में एक सामूहिक इकाई के रूप में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना है। भारतीय पुरुष टीम को पूल-ए में मौजूदा ओलंपिक चैंपियन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, स्पेन और मेजबान जापान के साथ रखा गया है। यह टूर्नामेंट 23 जुलाई से 5 अगस्त तक टोक्यो में होगा।

भारतीय टीम :

गोलकीपर : पी आर श्रीजेश

डिफेंडर : हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, बीरेंद्र लकड़ा

मिडफील्डर: हार्दिक सिंह, मनप्रीत सिंह, विवेक सागर प्रसाद, नीलकांत शर्मा, सुमित

फारवर्ड : शमशेर सिंह, दिलप्रीत सिंह, गुरजंत सिंह,ललित कुमार उपाध्याय, मनदीप सिंह

यूरो कप : बेल्जियम ने डेनमार्क को 2-1 से हराया

कोपेनहेगन। बेल्जियम ने शनिवार को खेले गए यूरो कप 2020 मुकाबले में डेनमार्क को 2-1 से हरा दिया। बेल्जियम की टीम ने इस जीत को अपने स्टार डिफेंडर क्रिस्टीयन एरिक्सन को समर्पित किया। एरिक्सन फिनलैंड के साथ हुए पहले मैच में मैदान पर गिर पड़े थे। मैच रोक दिया गया था और एरिक्सन को अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी हालत अब स्थिर है। यूसुफ पालसेन ने दूसरे मिनट में ही गोल करते हुए डेनमार्क को आगे कर दिया था। डेनिश टीम इस गोल को 53वें मिनट तक बरकरार रखने में सफल रही लेकिन 54वें मिनट में गोल कर थॉर्गन हाजार्ड ने स्कोर बराबर कर दिया। इसके बाद बेल्जियम की टीम ने आगे निकलने की कोशिश जारी रखी। 70वें मिनट में आखिरकार उसे सफलता मिल ही गई। मैनचेस्टर सिटी के लिए खेलने वाले केविन दे ब्रूएन ने इस गोल के साथ अपनी टीम को आगे कर दिया। बेल्जियम अपने ग्रुप में टॉप पर है। डेनमार्क का अभी जीत का खाता नहीं खुला है।

अरबी की उन्नत आर्गनिक जैविक खेती

अरबी एक बहुवर्षीय कंदीय फसल है। इसके बड़े आकार के पत्तों एंव कंद (गांठों)को सब्जी के रूप में खाते है। इसकी खेती मुख्यत: 1600 मीटर तक की ऊँचाई वाले क्षेत्रों में की जाती है। इन क्षेत्रों के लगभग सभी परिवार इसको गृह–वाटिका में उगाते हैं। अरबी अच्छे भाव बिकती है तथा इसका भण्डारण काफी समय तक कमरों में ही किया जा सकता है।

अरबी कि फसल को गर्म और आर्द्र जलवायु कि आवश्यकता होती है यह ग्रीष्म और वर्षा दोनों मौसमों में उगाई जा सकती है इसे उष्ण और उप उष्ण देशों में उगाया जा सकता है उत्तरी भारत कि जलवायु अरबी कि खेती के लिए सर्वोत्तम मानी गई है।

भूमि

अरबी के लिए पर्याप्त जीवांश वाली रेतीली दोमट मिटटी अच्छी रहती है इसके लिए गहरी भूमि होनी चाहिए ताकि इसके कंदों का समुचित विकास हो सके

प्रजातियाँ

आजकल भी अरबी कि स्थानीय किस्मे उगाई जाती है देश के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ स्थानीय किस्मे उगाई जाती है अब कुछ उन्नत किस्मे भी उगाई जाने लगी है .

फैजाबाद, लाधरा वंशी, बंगाली बड़ा, देशी बड़ा, पंचमुखी, गुर्री काचू, आस काचू, काका काचू, सर काचू, एन.डी.सी.-1, एन.डी.सी.-2

बोने का समय

अरबी कि बुबाई फरवरी, मार्च, जून जुलाई में की जाती है

बीज की मात्रा

अरबी के लिए 8-10 क्विंटल बीज प्रति हे 0 कि फदर से उप्योद करे बुबाई के लिए केवल अंकुरित बीज का उपयोग करे।

बोने की विधि

अरबी कि बुबाई निम्नलिखित दो बिधियों से की जाती है .

समतल क्यारी

भली भाँती तैयार करके पंक्तियों कि आपसी 45 से 0 मि 0 और पौधों कि आपसी दुरी दुरी 30 से 0 मि 0 रखकर बीज बलि गांठों को 7.5 से 0 मि 0 गहराई पर मिटटी के अन्दर बो दे .

डौलों पर

45 से.मी. की दुरी पर डौलीयां बनायें डौलीयों के बिच दोनों किनारों 30 पर से.मी. की दुरी पर गांठे बो दें।

कन्दों को एक पंक्ति से दूसरी पंक्ति की दूरी 30-45 सैं. मी. तथा कंद से कंद की दूरी 20-30 सैं. मी. रखें तथा 5-6 सैं. मी. गहराई में बोयें। बीजाई के लिए 50-60 ग्राम भर वाले कन्दों का प्रयोग करें। बड़े कन्दों को काटकर प्रयोग किया जा सकता है। प्रत्येक टुकड़े में 1-2 आँखे होनी चाहिए। बीजाई के तुरन्त बाद घास पत्तियों या गोबर की खाद से ढकना आवश्यक है।

सिंचाई व निराई-गुड़ाई

गर्मी की फसल में सिंचाई हर सात दिन बाद तथा वर्षा) ऋतु की फसल में सिंचाई वर्षा बीत जाने पर हर 10 दिन के बाद करनी चाहिए । फसल की एक दो बार उथली गुड़ाई करें तथा प्रत्येक निराई के बाद खुली हुई जड़ों और कन्दों के ऊपर मिट्टी चढ़ा देनी चाहिए ।

आर्गनिक जैविक खाद

गोबर की सड़ी हुयी खाद 25-30 टन प्रति हे . खेत में सामान मात्रा में बिखेर कर जुताई कर आर्गनिक 2 बैग भू पावर 50 किलो ग्राम, 2 - बैग माइक्रो फर्टी सिटी कम्पोस्ट वजन 40 किलो ग्राम, 2 - बैग माइक्रो भू पावर 10 किलोग्राम वजन, वजन खाद 2 बैग सुपर गोल्ड कैल्सी फर्ट वजन 10 किलो ग्राम, 2 बैग माइक्रो नीम वजन 20 किलो ग्राम और 50 किलो ग्राम अरंडी कि खली इन सब खादों को मिला कर मिश्रण तैयार कर प्रति एकड़ खेत में सामान मात्रा में बिखेर कर जुताई कर खेत तैयार कर बुवाई करें।

फसल 20 - 25 दिन कि हो जाये तब 2 किलो सुपर गोल्ड मैग्नीशियम 500 मी.ली. माइक्रो झाइम 400 लीटर पानी में मिलाकर अच्छी तरह घोलकर पम्प द्वारा तर बतर कर छिड़ काव करे दूसरा और जब - तीसरा हर छिड़काव 20 - 25 दिन पर लगातार करते रहें।

सिंचाई

ग्रीष्म ऋतु की फसल को अधिक सिचाइयों कि आवश्यकता होती है जबकि वर्षा ऋतु वाली फसल को कम सिचाइयों कि आवश्यकता पड़ती है गर्मियों में सिचाई 6-7 दिन के अंतर से 10-12 करते रहना चाहिए और वर्षा वाली फसल कि सिचाई दिन या आवश्यकतानुसार करते रहना चहिये अंतिम जून या जुलाई के प्रथम सप्ताह तक मिटटी चढ़ा देनी चाहिए यदि तने अधिक मात्रा में निकल रहे हों तो एक या दो मुख्य तनों को छोड़कर शेष सभी छटाई कर देनी चाहिए .

खरपतवार नियंत्रण

आवश्यकतानुसार प्रत्येक सिचाई के बाद - निराई गुड़ाई करे आमतौर पर 2-3 बार निराई गुड़ाई करने से काम चल जाता है .

कीट नियंत्रण

अरबी कि पत्तियां खाने वाले कीड़ों (सुंडी व मक्खी) द्वारा हानी होती है क्योंकि ये कीड़े नयी पत्तियों को खा जाते है .

रोकथाम

नीम का काढ़ा या गौ मूत्र का माइक्रो झाइम के साथमिलाकर छिडकाव करे .

रोग नियंत्रण

अरबी का झुलसा– यह रोग फाइटोफ्थोरा कोलोकेसी नामक फफूंदी के कारण होता है इसका प्रकोप - जुलाई अगस्त में होता है पत्तियों पर पहले गोल काले धब्बे पड़ जाते है बाद में पत्तियां गलकर गिर जाती है कंदों का निर्माण बिलकुल नहीं होता है।

रोकथाम

उचित फसल चक्र अपनाना चाहिए, रोगी पौधों को उखाड़ कर जाला देना चाहिए। नीम का काढ़ा या गौ मूत्र का माइक्रो झाइम के साथ मिलाकर लगातार 15 - 20 दिन के अंतराल पर छिड़काव करते रहना चाहिए।

नीम का काढ़ा

25 ग्राम नीम कि पत्ती ताजा हरा तोड़कर कुचल कर पिस कर किलो 50 लीटर पानी में पकाएं जब पानी 20 - 25 लीटर रह जाये तब उतार कर आधा लीटर प्रति पम्प पानी में मिलाकर प्रयोग करे।

गौ मूत्र

देसी गाय का गौ मूत्र 10 लीटर लेकर पारदर्शी बर्तन कांच या प्लास्टिक में लेकर 10 - 15 दिन धुप में रख कर आधा लीटर प्रति पम्प पानी मिलाकर प्रयोग करे।

खुदाई

अरबी कि जड़ों कि खुदाई का समय जड़ों के आकार, जाति, जलवायु और भूमि कि उर्बर शक्ति पर निर्भर करता है इसकी फसल बोने के लगभग 3 महीने बाद खुदाई के लिए तैयार हो जाती है पत्तियां सुख जाती है तब उनकी खुदाई करनी चाहिए .

उपज

प्रति हे 0 300-400 क्विंटल तक उपज मिल जाती है ।

भण्डारण

अरबी कि गांठों को ऐसे कमरे में रखना चाहिए जहा गर्मी न हो गांठों को कमरे में फैला दे गाठों को कुछ दिन के अंतरसे पलटते रहना चाहिए सड़ी हुयी गांठों को निकालते रहें इस प्रक्रिया से मिटटी भी झड जाती है आवश्यकतानुसार बाजार में बिक्री के लिए भी निकालते रहे - कही कही अरबी को सुखाने बाद स्वच्छ बोरों में भरकर भंडार गृह में रखते है

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

विवादित अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों की इजराइल पुलिस के साथ हुई झड़प

यरूशलम। यरूशलम में अल-अक्सा मस्जिद के परिसर में जुमे के नमाज के बाद फलस्तीनियों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उनकी इजराइल पुलिस के साथ छिटपुट झड़प हुई, जिसमें तीन प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इससे पहले अप्रैल और मई में सिलसिलेवार हिंसक झड़पों के बाद पिछले महीने इजराइल और गजा के बीच 11 दिन तक लड़ाई चली थी। अल-अक्सा मस्जिद इस्लाम में तीसरा सबसे पवित्र स्थल है जबकि बाइबिल में वर्णित मंदिरों का स्थान होने के चलते यहूदी इसे टेम्पल माउंट कहते हैं। यहां अकसर इजराइली और फलस्तीनियों के बीच हिंसा देखी जाती रही है। इस बार पुलिस ने परिसर में प्रवेश से परहेज किया और ज्यादा धैर्य के साथ काम लेती हुई दिखाई दी। रेड क्रिसेंट इमरजेंसी सर्विस ने कहा कि रबड़ बुलेट से दो फलस्तीनी घायल हो गए जबकि तीसरा व्यक्ति पत्थर लगने से जख्मी हो गया। इस दौरान फलस्तीनी युवा परिसर के प्रवेश स्थल के पास खड़े पुलिसकर्मियों पर पत्थर फेंकते हुए दिखाई दिये। वहीं दूसरी ओर पुलिस ने ग्रेनेड और रबड़ बुलेट का इस्तेमाल किया। मंगलवार को हुई यहूदी अति राष्ट्रवादियों की रैली के जवाब में शुक्रवार की नमाज के बाद सैंकड़ों लोगों ने प्रदर्शन किया। बताया जा रहा है कि यहूदी अति राष्ट्रवादियों की रैली में अरबों तुम्हारी मौत आए और तुम्हारी बस्ती जल जाए जैसे नारे लगाए गए थे।

म्यांमार को हथियारों की आपूर्ति पर रोक, लोकतंत्र बहाली के यूएन प्रस्ताव को मंजूरी मिलने की संभावना

संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा उस प्रस्ताव को मंजूरी दिये जाने की संभावना है, जिसके जरिए म्यामांर के सैन्य शासन से देश में लोकतंत्र बहाल करने की अपील की गई है। साथ ही, इसमें अन्य सभी देशों से म्यामां को हथियारों की आपूर्ति पर रोक लगाने को भी कहा गया है। मसौदा प्रस्ताव में सुरक्षा बलों द्वारा की गई हिंसा की भी निंदा की गई है और सैन्य शासन से अपदस्थ असैन्य नेता आंग सान सू ची, राष्ट्रपति विन मयिंत और मनमाने तरीके से हिरासत में लिये गये, आरोपित या गिरफ्तार किये गये सभी लोगों की बिना शर्त रिहाई की अपील की गई है। संयुक्त राष्ट्र की 193 सदस्यीय महासभा द्वारा प्रस्ताव पर शुक्रवार दोपहर विचार करने का प्रस्ताव है, जिनमें से 50 से अधिक देश इस प्रस्ताव के सह प्रायोजक हैं। प्रस्ताव के प्रायोजकों को उम्मीद है कि इसे आम सहमति से मंजूरी मिल जाएगी, जिससे एक फरवरी को सैन्य तख्तापलट करने वालों को एक सख्त संदेश मिलेगा और लोकतंत्र बहाली को समर्थन मिलेगा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के उलट महासभा के प्रस्ताव कानूनी रूप से बाध्य नहीं हैं लेकिन वे वैश्विक राय को प्रदर्शित करते हैं। गौरतलब है कि पिछले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने उन विश्वसनीय खबरों का हवाला दिया था, जिनमें कहा गया है कि सुक्षा बलों द्वारा एक फरवरी से 860 से अधिक लोग मारे गये हैं।

पुर्तगाली राजधानी के निवासियों को क्षेत्र छोड़ने की अनुमति नहीं

लिस्बन । पुर्तगाली सरकार ने घोषणा की कि लिस्बन का पूरा महानगर क्षेत्र देश की राजधानी में कोविड 19 पुनरुत्थान को रोकने के लिए शुक्रवार से(एएमएल) सप्ताहांत पर दोपहर 3 बजे से 21 जून को सुबह 6 बजे तक आईसोलेट रहेगा। सिन्हुआ समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार प्रेसीडेंसी राज्य मंत्री, मारियाना विएरा द सिल्वा ने गुरुवार को कहा कि एएमएल में संचलन पर प्रतिबंध का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि इस क्षेत्र में महामारी की उच्च घटना इससे बाहर और कहीं नहीं है। राजधानी में गतिविधियों और घटनाओं के सामान्य निरीक्षण के सुदृढ़ीकरण के साथ, मंत्री ने कहा कि प्रतिबंध एएमएल में 18 नगर पालिकाओं को प्रभावित करता है। डा सिल्वा के अनुसार, महामारी को नियंत्रित करने के लिए यह एक नया उपाय है और क्षेत्र में डेल्टा संस्करण की व्यापकता के कारण कोविड की घटनाओं में वृद्धि को रोकने के लिए आवश्यक भी है।

न्यूजीलैंड की पीएम ने ली कोरोना के खिलाफ वैक्सीन

वेलिंग्टन, 18 जून (आईएएनएस)। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा अर्डर्न को शुक्रवार को ऑकलैंड में कोविड-19 वैक्सीन की पहली खुराक लीं।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, अर्डर्न ने कहा कि फ्लू का टीका लेने के मुकाबले वैक्सीन लेना सहज है। उन्होंने आगे कहा, मैं पहले टीका

लगवाने वाली इंसान नहीं, बल्कि मैं रोल मॉडल बनना चाहती थी। मैंने इस क्षण टीका लगवाने का फैसला इस वजह से लिया ताकि यह दिखाने में अपनी भूमिका का निर्वहन कर सकूं कि मैं इसे अपने लिए सुरक्षित मानती हूं और यह भी मानती हूं कि दूसरों को सुरक्षित रखने में भी यह महत्वपूर्ण है। गुरुवार को न्यूजीलैंड की आम जनता के लिए वैक्सीन रोलआउट की योजना की घोषणा की गई। यहां 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों का टीकाकरण 28 जुलाई से और 55 वर्ष से अधिक आयु वालों का टीकाकरण 11 अगस्त से किया जाएगा। अर्डर्न ने कहा, हमारा टीकाकरण कार्यक्रम योजना से आगे है। लगभग दस लाख खुराकें दी जा चुकी हैं और लक्ष्य को हासिल करने के लिए 107 फीसदी की दर से काम किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि न्यूजीलैंड के हर एक योग्य नागरिक को साल के अंत तक टीकाकरण करवाने का अवसर मिलेगा।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अमेरिका को दी खुली चुनौती, टकराव की स्थिति

सियोल। (एजेंसी)।

उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने अपनी सरकार को अमेरिका में जो बाइडन प्रशासन से संवाद और टकराव दोनों के लिए तैयार रहने को कहा है। सरकारी मीडिया ने शुक्रवार को यह खबर दी। कुछ दिन पहले ही अमेरिका और अन्य देशों ने उत्तर कोरिया से अपना परमाणु कार्यक्रम छोड़कर बातचीत का रास्ता फिर से अपनाने पर जोर दिया था। कुछ विशेषज्ञों ने कहा कि किम का बयान यह दर्शाता है कि वह अपने परमाणु हथियार के जखीरे को मजबूती से बढ़ाना चाहते हैं और अमेरिका पर उसकी नीतियों को छोड़ने का दबाव बनाना चाहते हैं जिसे उत्तर कोरिया शत्रुतापूर्ण नीति बताता है।

हालांकि किम बातचीत बहाल करने के लिए भी तैयार हैं। देश में चल रही सत्तारूढ़ पार्टी की बैठक में बृहस्पतिवार को किम ने जो बाइडन के नेतृत्व में अमेरिकी नीतियों का विस्तार से विश्लेषण किया। किम ने इस दौरान संवाद और टकराव दोनों के लिए तैयार रहने की आवश्यकता पर जोर दिया। विशेषकर देश की प्रतिष्ठा की रक्षा और स्वतंत्र रूप से विकास के हितों तथा देश की सुरक्षा एवं शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने की खातिर टकराव की स्थिति के लिए तैयार रहने का आदेश दिया।

कूलभूषण के लिये कानून पारित करने का उद्देश्य आईसीजे के आदेश को अमल में लाना है: पाकिस्तान

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

पाकिस्तान ने बृहस्पतिवार को कहा कि मौत की सजा सुनाए गए भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव को अपील का अधिकार प्रदान करने के लिये नेशनल असेंबली में हाल ही में कानून पारित करने का उद्देश्य अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेश को पूरी तरह अमल में लाना है। हेग स्थित अंतरराष्ट्रीय न्यायालय ने जुलाई 2019 में फैसला सुनाया था कि पाकिस्तान को जाधव के दोष और सजा की प्रभावी समीक्षा और पुनर्विचार करना चाहिए और बिना किसी देरी के भारत को राजनयिक पहुंच प्रदान करनी चाहिये। भारत ने बृहस्पतिवार को पाकिस्तान से कहा कि वह जाधव के अपील के अधिकार संबंधी नेशनल एसेम्बली द्वारा पारित विधेयक की खामियों को दूर करने के लिये समुचित कदम उठाये। भारत ने कहा कि कानून में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे जाधव के मामले में प्रभावी समीक्षा एवं पुनर्विचार की सुविधा प्रदान की जा सके जैसा कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के फैसले में कहा गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के

प्रवक्ता जाहिद हाफिज चौधरी से इस्लामाबाद में साप्ताहिक मीडिया ब्रीफिंग में पिछले सप्ताह नेशनल असेंबली में पारित कानून के बारे में पूछा गया।

उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने आईसीजे के आदेश को पूरी तरह अमल में लाने के लिये ही यह कानून पारित किया। चौधरी ने कहा, कानून या इसके उद्देश्य का किसी भी तरह से गलत मतलब नहीं निकाला जाना चाहिये।

अब श्रीलंका में मिला कोरोना वायरस का डेल्टा वैरिएंट, टीके की एक खुराक हो सकती बेअसर!

कोलंबो। (एजेंसी)।

श्रीलंका में अधिकारियों ने कहा है कि देश में समुदाय के भीतर कोरोना वायरस का बेहद संक्रामक डेल्टा स्वरूप पहली बार पाया गया है। श्री जयवर्धनपुरा विश्वविद्यालय में इम्युनोलॉजी एवं मॉलिक्यूलर मेडिसीन विभाग में एलर्जी इम्युनोलॉजी एवं सेल बायोलॉजी इकाई की निदेशक डॉ. चंदिमा जीवंदरा ने बताया कि वायरस का यह स्वरूप कोलंबो के उपनगर देमातागौड़ा के इलाके से लिए गए नमूनों में पाया गया है। जीवंदरा ने बताया, ''हमने देमातागौड़ा से आठ नमूने लिए थे जिनमें पांच कोरोना वायरस के डेल्टा स्वरूप से संक्रमित पाए गए हैं। अलग-अलग पीसीआर जांच किट के जरिए हम वायरस के अलग-अलग स्वरूपों पर लगातार नजर रखते हैं।'' यह पहली बार है जब समुदाय में कोरोना वायरस का यह स्वरूप मिला है, इससे पहले दो लोग डेल्टा स्वरूप से संक्रमित

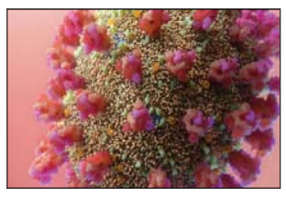

पाए गए थे लेकिन वे एक पृथक-वास केंद्र में थे।

विश्वविद्यालय की एक पहले की रिपोर्ट में कहा गया था कि देश में पाए जा रहे अल्फा स्वरूप के मुकाबले डेल्टा स्वरूप 50 फीसदी अधिक संक्रामक है और यह अधिक गंभीर रोग करने में सक्षम है तथा टीके की एक खुराक इस पर बेअसर हो सकती है। डेल्टा स्वरूप की सबसे पहले पहचान भारत में हुई थी, इसे कोरोना वायरस का अत्यधिक संक्रामक स्वरूप माना जाता है। श्रीलंका में अप्रैल माह से ही संक्रमण के मामलों तथा मरने वालों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो रही है। यहां अब तक संक्रमण के कुल 2,30,692 मामले हैं तथा 2,374 लोगों की मौत हो चुकी है।

क्या कोविड वैक्सीन से पुरुषों की प्रजनन क्षमता को पहुंचता है नुकसान? पढ़े ये रिपोर्ट

वाशिंगटन। फाइजर और मॉडर्ना के कोविड-19 टीकों से पुरुषों की प्रजनन क्षमता को नुकसान नहीं होने का दावा करने वाले एक अध्ययन में पाया गया कि इसमें प्रतिभागी लोगों को टीके की दो खुराक लगने के बाद भी उनके शुक्राणुओं के स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ा। 'जामा' जर्नल में बृहस्पतिवार को प्रकाशित अध्ययन में 18 से 50 वर्ष के 45 स्वस्थ लोगों को शामिल किया गया जिन्हें फाइजर-बायोएनटेक और मॉडर्ना के एमएआरएनए कोविड-19 टीके लगने थे। इस अध्ययन में प्रतिभागियों की पूर्व में ही जांच कर यह भी पता लगाया कि उन्हें पहले से कोई प्रजनन संबंधी समस्या नहीं हो। इसमें 90 दिन पहले तक कोविड-19 से ग्रस्त हुए या उसके लक्षण वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया। इसमें पुरुषों को टीके की पहली खुराक लगाये जाने से पहले उनके वीर्य के नमूने लिये गये और दूसरी खुराक के करीब 70 दिन बाद नमूने लिये गये। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशानिर्देशों के अनुसार प्रशिक्षित विशेषज्ञों ने विभिन्न मानकों पर शुक्राणुओं की जांच की। अध्ययन के लेखकों में शामिल अमेरिका की मियामी यूनिवर्सिटी के एक अध्ययनकर्ता ने कहा, ''टीका लगवाने में लोगों की हिचक का एक कारण प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर होने की धारणा भी है।

कोरोना से भारत में हुई तबाही के लिए ट्रंप ने चीन को बताया जिम्मेदार, कहा- देना चाहिए हर्जाना

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

कोरोना से भारत में हुई तबाही को लेकर पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ सेस बड़ा बयान सामने आया है। ट्रंप ने कहा कि कोरोना से भारत में हुई तबाही के लिए चीन जिम्मेदार है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने कोरोना की वजह से भारत में मची तबाही का जिक्र करते हुए चीन को जिम्मेदार बताया। इसके साथ ही ट्रंप ने कहा कि चीन को अमेरिका को 10 खबर डॉलर का हर्जाना देना चाहिए। चीन को अभी भी पूरी दुनिया को हर्जाना देना चाहिए। गौरतलब है क डोनाल्ड ट्रंप लगातार चीन को लेकर हमलावर रहे हैं और उन्होंने कहा भी था कि चीन से ही कोरोना वायरस की उत्तपत्ति हुई है। कोरोना वायरस के फैलने को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में फॉक्स न्यूज से बात करते हुए ट्रंप ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि यह एक दुर्घटना थी। मुझे उम्मीद है कि यह अक्षमता या दुर्घटना के कारण हुआ था। इस दौरान पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर इससे पहले किसी भी बीमारी से इतनी मौतें नहीं हुईं। आप देख सकते हैं क अभी भारत में क्या हो रहा है। ऐसी

ही स्थिति से कई अन्य देशों को भी गुजरना पड़ा है. लिहाजा, जो इस तबाही का कारण है उससे हर्जाना वसूला जाना चाहिए। इससे पहले भी ट्रंप चीन को लेकर हमलावर रहे हैं चाहे वो कोरोना वायरस को वुहान वायरस कहना हो या फिर चाइन वायरस कहकर पुकारे जाना। बीते दिनों राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के स्त्रोत को लेकर एक बार फिर से चीन और उसकी वुहान लैब पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा था कि वुहान की लैब से चीनी वायरस के निकलने के अनुमान के मामले में मैं सही था। उन्होंने कहा, 'अब हर कोई यहां तक कि दुश्मन भी यह कहना शुरू कर चुके हैं कि राष्ट्रपति ट्रंप का चाइना वायरस के वुहान की लैब से आने की बात सही थी।

नेपाल की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने कहा- सुप्रीम कोर्ट उनका फैसला नहीं पलट सकता

काठमांडू। (एजेंसी)।

नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने उच्चतम न्यायालय में कहा है कि प्रतिनिधिसभा को संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप ही भंग किया गया है और इस मामले में न्यायालय उनके फैसले को पलट नहीं सकता है और न ही इसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है। राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने प्रधानमंत्री के. पी. शर्मा ओली की सिफारिश पर पांच महीने में दूसरी बार 22 मई को प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया और 12 तथा 19 नवंबर को मध्यावधि चुनाव कराने की घोषणा की।प्रधानमंत्री ओली प्रतिनिधि सभा में विश्वास मत हारने के बाद अल्पमत सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं।

'काठमांडू पोस्ट' की खबर के मुताबिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष अग्नि सपकोटा ने सरकार के 21 मई के फैसले के बारे में शीर्ष अदालत में अपने-अपने स्पष्टीकरण लिखित में पेश किए हैं। न्यायालय की संवैधानिक पीठ ने नौ जून को उनसे लिखित स्पष्टीकरण देने को कहा था। इसमें राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने जहां अपने फैसलों का बचाव किया है वहीं प्रतिनिधि सभा के अध्यक्ष ने इसे असंवैधानिक कदम बताया है। राष्ट्रपति कार्यालय 'शीतल निवास' की ओर से कहा गया है कि राष्ट्रपति के फैसले की न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती है।

अटॉर्नी जनरल कार्यालय की ओर से न्यायालय को उपलब्ध करवाए गए स्पष्टीकरण में राष्ट्रपति ने कहा है, ''संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति का कोई भी कदम याचिका का विषय नहीं बन सकता है तथा यह न्यायिक समीक्षा का मुद्दा भी नहीं बन सकता है।'' भंडारी ने 'राष्ट्रपति एवं उप राष्ट्रपति को पारितोषिक एवं लाभ अधिनियम 2017' के अनुच्छेद 16 का जिक्र किया जो कहता है कि राष्ट्रपति के किसी भी कदम को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रपति ने कहा, ''अतः राष्ट्रपति द्वारा बिना किसी की सिफारिश के संविधान के आधार पर लिए गए किसी भी निर्णय पर अदालत कोई कार्रवाई नहीं कर सकती है।'' वहीं, ओली ने कहा कि सरकार गठन एक राजनीतिक प्रक्रिया और इस बारे में अदालत फैसला नहीं ले सकती है। प्रतिनिधि सभा को भंग करने के खिलाफ विपक्षी गठबंधन की याचिका सहित 30 रिट याचिकाएं दायर की गई हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि प्रतिनिधि सभा को भंग किया जाना ''असंवैधानिक'' है।

अमेरिका ने दिए अफगानिस्तान में दूतावास बंद करने के आदेश,कोरोना के बढ़ रहे केस

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अफगानिस्तान में अमेरिका के दूतावास ने अपने कर्मचारियों के बीच कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के कारण उसे लगभग पूरी तरह बंद करने के आदेश दिए हैं। देश से अमेरिकी सैनिकों के लौटने का वक्त नजदीक आने के कारण पहले से ही अनिश्चितता की स्थिति वाले दूतावास ने काबुल में बृहस्पतिवार को बाकी बचे कर्मियों को कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोकने के लिए अलग होने के आदेश दिए हैं। दूतावास में संक्रमण से एक कर्मचारी की मौत हो चुकी है और 114 कर्मचारी पृथक-वास में हैं। इसके अलावा कई लोगों को चिकित्सा संबंधी वजहों से दूतावास छोड़ना पड़ा है।

दूतावास ने कर्मचारियों को दिए गए एक नोटिस में कहा कि कामकाजी बैठकों और मनोरंजन सभाओं समेत सभी सामूहिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है क्योंकि अफगानिस्तान में सेना के अस्पतालों में आईसीयू में अब जगह नहीं है और मामले बेतहाशा बढ़ने के कारण उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता वाले मरीजों की

देखभाल के लिए अस्थायी कोविड-19 वार्ड बनाने पड़े हैं। नोटिस के अनुसार, जब तक संक्रमण की श्रृंखला नहीं टूटती तब तक पार्बंदियां लागू रहेंगी। उल्लंघकर्ताओं को देश से वापस बुला लिया जाएगा। नोटिस में कहा गया है कि संक्रमण के 95 प्रतिशत मामले ऐसे लोगों के हैं जिन्होंने टीका नहीं लगवाया। दूतावास ने सभी कर्मियों से, दूतावास में उपलब्ध टीकों की खुराक लेने का आग्रह किया। अमेरिका के कार्यवाहक राजदूत रॉस विल्सन ने कहा, ''हम सभी के सहयोग से ही सामान्य कामकाज बहाल कर सकते हैं।''इन पाबंदियों के चलते काबुल में स्थित दूतावास के सभी कर्मचारी अपने क्वार्टर में ही रहेंगे और केवल भोजन लाने या व्यायाम करने के लिए ही बाहर निकलेंगे।

इजराइली सेना में गुजराती मूल की नित्शा, हमास हवाई हमले में निभाया अहम किरदार

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

मॉरीन फेरान, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ बापिछले महीने 11 दिनों तक चले इजराइल और हमास के बीच युद्ध का अंत एक सीजफायर समझौते से हुआ था लेकिन एक बार फिर से संघर्ष शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि इजराइल मे गाजा पट्टी पर हवाई हमले करते हुए कई रॉकेट दागी है। फिलीस्तीनी एन्क्लेव से आग लगाने वाले गुब्बारे दागे के बाद इजराइल ने मंगलवार को हवाई हमला किया। इस हवाई हमले में गुजराती मूल की 20 वर्षीय युवती भी शामिल थीं। जिनका नाम नित्शा मुलियाशा बताया जा रहा है। नित्शा मुलियाशा इजराइली डिफेंस फोर्सेज टीम का हिस्सा हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नित्शा मुलियाशा राजकोट के मानवादार तालुका के कोठाड़ी गांव की रहने वाली हैं और अब तेल अवीव में बस गई हैं। इतना ही नहीं नित्शा मुलियाशा इजराइली सेना की सूची में शामिल होने वाली पहली गुजराती युवती हैं। नित्शा मुलियाशा के पिता जीवाभाई ने बताया कि यह सब इजराइली शिक्षा व्यवस्था की वजह से हो पाया है। उन्होंने बताया कि स्कूली शिक्षा के दौरान बच्चों को परखने के लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं। जिसकी बदौलत कॅरियर चुनने में सहूलियत होती है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नित्शा मुलियाशा को हथियारों के इस्तेमाल का कड़ा प्रशिक्षण मिला है। पिता जीवाभाई के मुताबिक सेना में एक बार 2.4 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद एक समझौते पर दस्तखत करना पड़ता है। जिसके बाद सैनिक अपनी मर्जी का कोर्स कर सकता है। आपको बता दें कि नित्शा मुलियाशा की पढ़ाई का पूरा खर्चा इजराइली सेना वहन करेगी। आपको बता दें कि नित्शा मुलियाशा की लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और मिस्र की सीमाओं पर तैनाती हो चुकी है और अब वह गुश डैन में मोर्चा तैनात हैं।

उल्लेखनीय है कि 11 दिनों तक चले इजराइली-हमास युद्ध में 253 फिलिस्तीनियों की मौत हुई थी। जिनमें 66 बच्चे भी शामिल थे और दर्जनों इमारतें जमीदोंज हो गई थीं। वहीं, 13 इजराइलियों ने भी जान गंवाई थी। इस दौरान दोनों के बीच रॉकेट और मिसाइल हमले हुए थे और एक बार फिर से हवाई हमला शुरू हो गया है।

सूरत में 'देख देख तेरा बाप आया' गाने पर बनी सचिन पुलिस की पीसीआर वैन का वीडियो वायरल

क्रांति समय दैनिक

सूरत पुलिस के बीच हुए विवाद के बीच सचिन की पीसीआर वैन का वीडियो वायरल हो गया है. हंगामा तब शुरूहुआ जब पता चला कि देख देख तेरा बाप आया सॉन्ग पर बनाए गए वीडियो में दिख रहा शख्स पुलिसकर्मी नहीं है. उच्च अधिकारियों द्वारा उस वीडियो की जांच के आदेश दिए गए थे, जिसे एक निजी व्यक्तिने पुलिस वैन में बनाया था।

वायरल वीडियो में पुलिस वैन होने से मामला गंभीर हो गया है

। जनता तो ठीक है, लेकिन पुलिस की पीसीआर वैन का वीडियो यह कहते हुए वायरल हो गया कि पुलिस भी सोशल मीडिया पर आ

गई है। प्राइवेट ड्रेस में एक युवक फिल्मी गाने के ऊपर पीसीआर वैन चला रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो ने जबरदस्त बहस छेड़ दी है. मामला तब गंभीर हो गया जब पता चला कि वैन सूरत पुलिस के सचिन थाने की है।

पुलिस वैन एक निजी व्यक्तिके पास कैसे गई ?

पुलिस द्वारा पीसीआर वैन में बनाए गए वीडियो की जांच के बीच उस समय काफी बवाल हो गया जब यह बात सामने आई कि पुलिस वैन चलाने वाला व्यक्तिपुलिसकर्मी नहीं बल्कि एक निजी व्यक्तिहै।

अधिकारियों द्वारा जल्दबाजी में जांच के आदेश जारी किए गए।

यह भी जांच का आदेश दिया गया था कि वैन पुलिस के बजाय एक निजी व्यक्तिके पास कैसे गई।

सूरत शहर में पिछले 24 घंटों में 3 इंच से बारिश हुई, इसके चलते सूरत के कई इलाकों में पानी भर गया

सड़कों पर नदियां बहती नजर आ रही हैं,सूरत में भारी बारिश से जलजमाव की एक झलक

क्रांति समय दैनिक

सूरत के डाभोली, पुनागाम, अर्चना स्कूल, भोली, लिबायंत गरनाला, कटारगाम जैसेनिचले इलाकों में कुछ जगहों पर घुटनों तक पानी भर गया . जिससे वाहन चालकों में हड़कंप मच गया। इतना ही नहीं कुछ जगहों पर तो घुटने तक पानी भर

क्रांति समय फाउंडेशन (NGO)

गया और कुछ लोगों के वाहन भी बारिश के पानी में फंस गए जो इस पानी को भर रहे थे.

रथयात्रा से पूर्व जलयात्रा को मंजूरी, केवल 5 कलश में नदी का जल लाया जाएगा

क्रांति समय दैनिक

भगवान जगन्नाथजी की रथयात्रा से पहले होनेवाली जलयात्रा को मंजूरी मिल गई है। आगामी 24 जून को अहमदाबाद के जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथजी के मंदिर जलयात्रा निकलेगी। इस वर्ष 108 कलश के बजाए केवल 5 कलश के साथ जलयात्रा के आयोजन का फैसला किया गया है। साथ ही जलयात्रा में अबकी बार कोई भजन मंडली शामिल नहीं होगी। इस वर्ष जल यात्रा में राज्य के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल और गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा शामिल होंगे। जलयात्रा में 50 से भी कम लोग होंगे और वह सभी मंदिर के सदस्य होंगे। सामान्य नागरिक अबकी बार जलयात्रा में शामिल नहीं हो सकेंगे। बता दें कि प्रति वर्ष अषाढी दूज को भगवान जगन्नाथजी की रथयात्रा का आयोजन किया जाता है। कोरोना महामारी के चलते पिछले वर्ष रथयात्रा को मंजूरी नहीं मिलने से अहमदाबाद के जमालपुर स्थित भगवान जगन्नाथजी के मंदिर में ही प्रतीक रथयात्रा निकाली गई थी। राज्यभर में कोरोना की दूसरी लहर का असर धीरे धीरे कम हो रहा है। हांलाकि इस साल रथयात्रा को मंजूरी मिलेगी यह फिलाहाल तय नहीं है। गृह राज्यमंत्री प्रदीपसिंह जाडेजा पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि रथयात्रा से पूर्व स्थिति को देखते हुए इसके आयोजन को मंजूरी दी जाएगी। फिलहाल तो जलयात्रा को मंजूरी मिल गई है, जो सीमित लोगों के साथ निकलेगी।

सार—समाचार

सगी भतीजी की चाची ने हत्या कर दी, पिता और चाचा मामले को छिपाया, तीनों गिरफ्तार

राजकोट,महिला चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है और न चाहे तो नर्क से बद्दतर बना देती है। उपलेटा में एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जिसमें परिवार की एक महिला की नफरत ने पूरे परिवार को छिन्नभिन्न कर दिया। बल्कि सगी भतीजी की हत्या कर पति और जेठ के साथ सलांखों के पीछे पहुंच गई। राजकोट के उपलेटा में सर्वोदय सोसायटी में दो भाई संयुक्तपरिवार में रहते हैं। जिसमें चेतन निमावत अपनी पत्नी किरण, 14 वर्षीय पुत्री काव्या और 9 वर्षीय पुत्री आयुषी शामिल है। छोटा भाई मयूर अपनी पत्नी वंदना, 13 वर्षीय पुत्र मानव और 8 वर्षीय मंत्र शामिल है। चेतन और मयूर उपलेटा में अशोक साबू नामक दुकान चलाकर परिवार का जीवनयापन करते हैं। गत 8 जून को दोपहर वंदना चीखपुकार सुनकर उसके जेठानी किरण बाहर दौड़कर आई तो देखा आयुषी लहूलुहान हालत में पड़ी है। गंभीर हालत में आयुषी को अस्पताल पहुंचाया गया। जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। खबर मिलते ही चेतन और मयूर भी अस्पताल पहुंच गए थे। दोनों पोस्टमार्टम कराए बगैर आयुषी को घर ले गए और बाद में स्मशान ले जाकर उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। आयुषी की मौत के बाद उसकी माता कोई काम से छत पर गई। जहां लहू से सना ब्लैंकेट और तौलिया देख उसे अपनी बेटी की हत्या की शंका हुई और वह तुरंत पुलिस थाने पहुंच गई। किरन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामले की जांच शुरूकर दी। पुलिस जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ था। आयुषी की हत्या उसकी सगी चाची वंदना की थी और उसके चाचा और पिता ने पूरा मामला रफादफा करने का प्रयास किया था। जांच में पता चला कि जेठानी किरन और देवरानी वंदना के बीच आए दिन लड़ाई–झगड़े होते रहते थे। वंदना का मोबाइल किरन भी उपयोग करती थी, जो वंदना को पसंद नहीं था। इन सब बातों से वंदना को किरन से इतनी नफरत हो गई कि गत 8 जून को वह आयुषी को छत पर ले गई और उसके सिर पर दस्ते से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। आयुषी के पिता चेतन ने समाज में बदनामी के डर से छोटे भाई मयूर की पत्नी का पाप छिपाया। इस खुलासे के बाद पुलिस ने मृतक आयुषी के पिता चेतन, चाचा मयूर और चाची वंदना को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरूकर दी।

Web site : www.krantisamay.com & .in , epaper.krantisamay.com www.facebook.com/krantisamay1 www.twitter.com/krantisamay1

सार समाचार

जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल ने 800 पुलिस उप-निरीक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दी

श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को जम्मू कश्मीर पुलिस में 800 उप-निरीक्षकों की भर्ती के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी जिससे कोविड-19 महामारी के कारण धीमी हुई भर्ती प्रक्रिया को गति मिल सकती है। यहां एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि चयन प्रक्रिया लिखित और शारीरिक परीक्षा पर आधारित होगी और सेवा चयन बोर्ड (एसएसबी) शारीरिक परीक्षण के लिए सरकार के साथ परामर्श करके एक समिति बनाएगा।
उन्होंने कहा, ''संपूर्ण भर्ती प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता तथा निष्पक्षता लाने के मकसद से किये जा रहे ऐतिहासिक सुधार की दिशा में उप राज्यपाल ने पुलिस, कारागार और दमकल सेवाओं के तीन विभागों में एसएसबी के माध्यम से सभी गैर-राजपत्रित स्तर के पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है।

राहुल के जन्मदिन पर एनएसयूआई और आईवाईसी करेंगे फ्री वैक्स कैंप

नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि वह अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगे। वहीं उनके जन्मदिन पर भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ और भारतीय युवा कांग्रेस ने लोगों के लिए अपने कार्यालय में मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान आयोजित करने की योजना बनाई है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीरज कुंदन ने आईएएनएस को बताया कि संगठन 19 जून को राहुल गांधी के जन्मदिन पर निशुल्क टीकाकरण अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि हमारे नेता राहुल जी का मानना है कि वायरस को फैलाने के बजाय हमें टीका लगवाना चाहिए ताकि वायरस न फैले। कुंदन ने कहा कि राहुल जी ने कहा है कि महामारी के बीच लोगों की सुरक्षा के लिए टीकाकरण सबसे अच्छा संभव तरीका है। एनएसयूआई के राष्ट्रीय सचिव लोकेश चुघ ने बताया कि शनिवार सुबह उनके कार्यालय में टीकाकरण शिविर शुरू होगा। उन्होंने कहा कि एनएसयूआई के कार्यकर्ता लोगों को कोविन साइट पर पंजीकृत कराने और उनका निशुल्क टीकाकरण कराने में मदद करेंगे।

ऑक्सीजन उत्पादन में आत्मनिर्भर बनेगा राजस्थान, 1000 टन का होगा उत्पादन

जयपुर। राजस्थान के चिकित्सा मंत्री डॉ. रघु शर्मा ने कहा है कि ऑक्सीजन उत्पादन के क्षेत्र में राजस्थान जल्द ही आत्मनिर्भर बन जाएगा। मंत्री ने कहा कि राज्य में विभिन्न संस्थानों द्वारा लगाए जा रहे ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्रों तथा अन्य उपकरणों के जरिए आने वाले दिनों में लगभग 1000 टन ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि दूसरी लहर में सबसे ज्यादा परेशानी ऑक्सीजन को लेकर देखने में आई। इससे निजात पाने के लिए सरकार ऑक्सीजन उत्पादन के लिये पुख्ता इंतजाम कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में विभिन्न जगहों पर लगाए जा रहे ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र, ऑक्सीजन कंस्ट्रेटर के जरिए पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन का उत्पादन किया जा सकेगा।

हरियाणा: आंदोलन में शामिल एक किसान को जिंदा जलाने का मामला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार

हिसार। हरियाणा के बहादुरगढ़ से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। जिसे सुनकर किसी की भी रुह कांप जाए लेकिन वारदात को अंजाम देने वाले का दिल भी नहीं पसीजा। दरअसल, बहादुरगढ़ इलाके में किसान आंदोलन में शामिल एक शख्स को जिंदा जला दिया गया है। इस मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। आरोपी कृष्ण जिंद जिले के गांव रायचन्द का रहने वाला है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस आज आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। आरोपी भी अपने साथियों के साथ पिछले काफी समय से किसान आंदोलन में शामिल था।

कर्नाटक के पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने मेकेदातु मुद्दा नहीं उठाने के लिए भाजपा पर साधा निशाना

बेंगलुरु। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी ने पार्टी की आंतरिक कलह में उलझे रहने के कारण मेकेदातु जलाशय परियोजना का मुद्दा नहीं उठाने के लिए सत्तारूढ़ भाजपा पर शुक्रवार को निशाना साधा। सिलसिलेवार ट्वीट में कुमारस्वामी ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने परियोजना को रोकने के लिए हाल में कदम उठाए थे जो कि कर्नाटक के हितों के खिलाफ है। जद (एस) नेता ने कहा, ''मेकेदातु जलाशय के साथ-साथ कावेरी नदी के संबंध में तमिलनाडु सरकार के कदम कर्नाटक के हितों के खिलाफ है।'' जद (एस) नेता ने कहा, ''राज्य की भाजपा सरकार को ऐसे मुद्दों पर गौर करना चाहिए लेकिन वह तो आंतरिक कलह से जूझ रही है।'' कुमारस्वामी के मुताबिक स्टालिन ने हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मेकेदातु जलाशय के निर्माण के लिए कर्नाटक को मंजूरी नहीं देने की अपील की थी। उन्होंने कहा, ''इस तरह की महत्वपूर्ण परियोजना अनिश्चितता की शिकार हो गयी है जबकि केंद्र और राज्य, दोनों जगह भाजपा की सरकार है। इससे भाजपा का वह दावा भी गलत साबित हो गया कि केंद्र और राज्य में एक पार्टी की सरकार रहने से स्वर्ग बन जाएगा। '' उन्होंने तमिलनाडु सरकार से मेकेदातु परियोजना को अनुमति देने की अपील करते हुए कहा कि इससे तमिलनाडु के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा।

कोरोना से जंग को तैयार होंगे 1 लाख वॉरियर्स, पीएम मोदी ने किया एक और महाअभियान का आगाज

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

कोविड-19 फ्रंटलाइन वर्करों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक क्रैश कोर्स लॉन्च किया। इसके साथ ही उन्होंने महामारी कोविड-19 को लेकर देश को तैयार रहने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आज शुरू किए जा रहे क्रैश कोर्स के जरिए 1 लाख वारियर्स को महामारी का सामना करने के लिए तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने क्रैश कोर्स करने वाले फ्रंटलाइन वर्करों को शुभकामनाएं दी और उम्मीद जताई की वे जल्द ही हेल्थकेयर वर्करों के सहयोग के लिए तैयार होंगे। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्कर्स के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए इस 'क्रैश कोर्स प्रोग्राम' का शुभारंभ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 के तहत देश भर के 26 राज्यों में स्थित 111 प्रशिक्षण केंद्रों में की जाएगी। लॉन्च के इस मौके पर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे।

2-3 महीने में पूरा होगा क्रैश कोर्स

यहां प्रधानमंत्री ने कहा, 'इस कोविड-19 महामारी ने दुनिया के हर देश, हर संस्था, हर समाज, हर परिवार, हर इंसान के सामर्थ्य को बार-बार परखा है। वहीं इस महामारी ने साइंस, सरकार, समाज, संस्था और व्यक्ति के रूप में हमें अपनी क्षमताओं का विस्तार करने के लिए सतर्क भी किया है।' पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से लड़ रही वर्तमान फोर्स को सपोर्ट करने के लिए देश में करीब 1 लाख युवाओं को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया है, ये कोर्स 2-3 महीने में ही पूरा हो जाएगा।

पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस अभियान से कोविड से लड़ रही हमारी हेल्थ सेक्टर की फ्रंट लाइन फोर्स को नई ऊर्जा भी मिलेगी और हमारे युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे, बीते 7 साल में देश में नए एम्स, नए मेडिकल कॉलेज, नए नर्सिंग कॉलेज के निर्माण पर बल दिया गया है, इनमें से कई ने काम करना भी शुरु कर दिया है। पीएमओ के मुताबिक इस कार्यक्रम का उद्देश्य देशभर में एक लाख से अधिक कोविड योद्धाओं को कौशल से लैस करना और उन्हें कुछ नया सिखाना है। इस कार्यक्रम को 276 करोड़ रुपये के कुल वित्तीय परिव्यय के साथ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना तृतीय के केन्द्रीय घटक के तहत एक विशेष कार्यक्रम के रूप में तैयार किया गया है। इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में श्रमशक्ति की वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए कुशल गैर-चिकित्सा स्वास्थ्यकर्मियों को तैयार किया जाएगा। किसी विषय विशेष की जानकारी देने और कौशल विकसित करने के मकसद से अल्प अवधि के लिए चलाये जाने वाले कार्यक्रम को क्रैश कोर्स कहते हैं।

कोरोना संक्रमण के मामलो में आई कमी, डॉ. हर्षवर्धन बोले- टेस्टिंग प्रक्रिया को नहीं होने दिया कमजोर

नई दिल्ली। (एजेंसी)।

कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचाया हुआ था। इस दौरान एक दिन में 4 लाख से अधिक मामले तक दर्ज किए गए थे। हालांकि, अब इन मामलों में कमी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने इससे जुड़ी हुई जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वायरस संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं फिर भी हमने टेस्ट करने की प्रक्रिया को कमजोर नहीं होने दिया है। समाचार एजेंसी के मुताबिक केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने कहा कि कोरोना की दूसरी वेव 4 लाख से ज़्यादा मामलों की ऊंचाई पर पहुंची, काफी दिनों से एक लाख से कम मामले आ रहे हैं। मामले कम हो रहे हैं, उसके बावजूद हमने अपनी टेस्ट करने की प्रक्रिया को कमजोर नहीं होने दिया। उन्होंने आगे कहा कि पिछले कई हफ़्तों से बहुत से स्थानों पर अलग-अलग प्रकार का लॉकडाउन चल रहा था और अब वो अनलॉक की प्रक्रिया में बदल रहा है। इस अनलॉकिंग में पहली वेव के बाद हमने जो ढील दी, वो गलती हमसे कहीं फिर ना हो जाए। उल्लेखनीय है कि देश में एक दिन में कोविड-19 के 62,480 नए मामले सामने आए। जिसके बाद संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,97,62,793 हो गई। वहीं, 1587 और लोगों की संक्रमण से मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 3,83,490 हो गई। पिछले 61 दिन में संक्रमण से मौत के ये सबसे कम मामले हैं।

महाराष्ट्र सरकार का आरोप, सीबीआई देशमुख के खिलाफ प्राथमिकी के जरिए शुक्ला मामले में दखल दे रही

मुंबई। (एजेंसी)।

महाराष्ट्र सरकार ने शुक्रवार को बंबई उच्च न्यायालय में कहा कि वह नहीं चाहती कि उसे राकांपा नेता अनिल देशमुख का बचाव करते हुए देखा जाए लेकिन सीबीआई राज्य के पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ अपनी जांच का दायरा बढ़ाकर आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला के खिलाफ जांच में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रही है। राज्य ने यह आरोप लगाते हुए अदालत का रुख किया है कि देशमुख के खिलाफ केंद्रीय एजेंसी द्वारा दर्ज प्राथमिकी के कुछ हिस्से गैर-जरूरी है और इसकी मंशा शिवसेना-कांग्रेस-राकांपा सरकार को ÷अस्थिर÷ करने की है।

महाराष्ट्र सरकार के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता रफीक दादा ने न्यायमूर्ति एस एस शिंदे और न्यायमूर्ति एन जे जामदार की खंडपीठ के समक्ष कहा कि राज्य कथित भ्रष्टाचार को लेकर देशमुख के खिलाफ सीबीआई की जांच में हस्तक्षेप नहीं करना चाहता। उन्होंने कहा कि राज्य सिर्फ यह चाहता है किप्रथम सूचना रिपोर्ट (प्राथमिकी) से कुछ अंश निकाल दिए जाएं। जब सीबीआई के वकील ने प्रस्ताव दिया कि अदालत को राज्य और देशमुख द्वारा दायर याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करनी चाहिए तो वकील रफीक दादा ने कहा, मैं श्री देशमुख का समर्थन करते हुए नहीं दिखना चाहता। वह अब मेरे मंत्री नहीं हैं। उन्होंने कहा कि सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वाजे की बहाली (अब बर्खास्त) और कुछ अन्य अधिकारियों के तबादले और तैनाती के मुद्दों को शामिल किया था जो मूल शिकायत का हिस्सा नहीं थे। दादा ने कहा कि वाजे की बहाली और तबादलों में देशमुख के कथित हस्तक्षेप के मुद्दों को शामिल कर सीबीआई उन मुद्दों की जांच करने की कोशिश कर रही है जिनकी राज्य पहले से ही जांच कर रहा है। उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को प्राथमिकी में शामिल करना आईपीएस अधिकारी रश्मि शुक्ला से जुड़े मामले में हस्तक्षेप करने का बहाना था। कथित अनधिकृत फोन टैपिंग और एक गोपनीय रिपोर्ट के लीक होने के मामले मेंराज्य की पूर्व खुफिया आयुक्त शुक्ला के खिलाफ जांच चल रही है। अदालत 21 जून को सीबीआई की दलीलों की सुनवाई करेगी। एजेंसी ने अदालत से कहा कि वह 22 जून तक देशमुख के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने के संबंध में दिए गए हलफनामे का पालन करने के लिए तैयार है।

मानसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर, लोकसभा अध्यक्ष बोले- 445 सांसदों का हो गया वैक्सीनेशन

नई दिल्ली। संसद का मानसून सत्र जुलाई में शुरू होगा। इसको लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मानसून सत्र का फैसला मंत्रिमंडलीय उपसमिति करती है, मुझे संभावना लगती है कि लोकसभा इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। लोकसभा कोविड गाइडलाइंस का पालन करेगी, पूरी तैयारियां हमने की हैं। लोकसभा

स्पीकर ने कहा कि संसद का मानसून सत्र चलेगा। सारी तैयारियां की गई हैं। 445 सांसदों को वैक्सीन की डोज़ लगी है। सचिवालय के सभी कर्मचारियों का भी वैक्सीनेशन हो गया है। जिन सांसदों और संसद में काम करने वाले लोगों को वैक्सीन की डोज़ नहीं लगी है उन्हें 21 जून से डोज़ लगेगी। मोदी सरकार का विधायी एजेंडा मानसून सत्र में व्यस्त होना तय है। सरकार ने सत्र के दौरान पारित होने के लिए प्रमुख विधेयकों की रूपरेखा तैयार कर ली है। अप्रैल और मई में आई महामारी की दूसरी लहर के अवसान के बाद आने वाले सत्र में संसद के समक्ष 40 से अधिक बिल और पांच अध्यादेश लंबित हैं। अब तक कम से कम 50 विधायक कोरोना संक्रमित हुए हैं और रेल राज्य मंत्री सुरेश अंगड़ी सहित तीन सांसदों की मौत हो चुकी है।

भारतीयों की स्विस बैंक में जमा राशि बढ़ने पर कांग्रेस ने सरकार को घेरा

नई दिल्ली (एजेंसी)।

कांग्रेस ने 2020 में भारतीयों द्वारा स्विस बैंक में जमा राशि में 286 प्रतिशत की वृद्धि की रिपोर्ट को लेकर सरकार पर हमला बोला है। मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आया है कि काले धन को वापस लाना तो दूर बल्कि इसमे अब रिकॉर्ड बढ़ोतरी दर्ज की गई है और भारतीयों की ओर से पिछले 13 साल में स्विस बैंक में जमा पैसा रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। इस पर कांग्रेस ने सरकार से पूछा है कि पिछले 7 सालों में किस देश से कितना काला धन वापस लाया गया? कांग्रेस ने मांग की कि मोदी सरकार उन व्यक्तियों के नाम साझा करे जिन्होंने पिछले एक साल में स्विस बैंकों में पैसा स्थानांतरित किया है? विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि 97 प्रतिशत भारतीय गरीब हो गए हैं, फिर ये कौन लोग हैं, जो आपदा में अवसर का लाभ उठा रहे हैं? विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने काले धन के प्रवाह को रोकने के

लिए कोई कदम नहीं उठाया है। एआईसीसी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, 2020 के लिए स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों और फर्मों द्वारा रखे गए फंड का डेटा स्विस नेशनल बैंक (एसएनबी) द्वारा जारी किया गया है। हम दृढ़ता के साथ कह रहे हैं कि मोदी सरकार के तहत अमीर और गरीब के बीच की खाई चौड़ी होती जा रही है। सीएमआईई के अनुसार, पिछले वर्ष के दौरान करीब 97 प्रतिशत भारतीय गरीब हो गए। उन्होंने कहा, 2020 के लिए स्विस बैंकों में फंड का डेटा कहानी का दूसरा पक्ष दिखाता है। 2019 की तुलना में 2020 में स्विस बैंकों में कुल जमा 286 प्रतिशत हो गया है। कुल जमा 13 साल के उच्च स्तर पर है, जो 2007 के बाद से सबसे अधिक है। बड़ा रहस्योद्घाटन बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट (बीआईएस) के आंकड़ों से हुआ है, जो स्विस बैंकों में व्यक्तियों द्वारा जमा को इंगित करता है। स्विस बैंकों में भारतीय व्यक्तियों द्वारा जमा 2019 की तुलना में 2020 में 39 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भाजपा ने 2014 में सत्ता संभालने से पहले दावा किया था कि भारतीय अकेले स्विस बैंकों में 250 अरब डॉलर (17.5 लाख करोड़ रुपये) छिपा रहे हैं। भाजपा ने यह भी वादा किया था कि वह विदेशी बैंकों में जमा काला धन वापस लाएगी और इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक भारतीय को 15 लाख रुपये मिलेंगे। पिछले 7 साल में मोदी सरकार सिर्फ बातें करती रही है कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास और परिणाम आपस में कोई मेल नहीं खा रहे हैं।

यूपी चुनाव की तैयारी में भाजपा, दलित और पिछड़ों को साधने की हो रही कोशिश

लखनऊ। (एजेंसी)।

उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा के चुनाव होने है। मिशन 2022 में कामयाबी की गाथा लिखने के लिए भाजपा अलग-अलग तरह की रणनीति बना रही है। साथ ही साथ इन रणनीति को अमल में लाने की भी कोशिश की जा रही है। दलित और पिछड़े वर्ग से आने वाले नेताओं को महत्वपूर्ण ओहदे सौंपे जा रहे है। हाल में ही उत्तर प्रदेश पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष सहारनपुर के जसवंत सैनी को बनाया गया है। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष आगरा के पुराने भाजपा नेता डॉक्टर रामबाबू हरित को बनाया गया है। इसके अलावा एससी एसटी आयोग में भी

सदस्यों को शामिल किया जा रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में नेतृत्व को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलों का बाजार गर्म है। इन सबके बीच संगठन में सबको साथ लेकर चलने की कवायद शुरू हो गई है। पुराने नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी अब शामिल किया जा रहा है। जसवंत सैनी के जरिए पिछड़े वर्ग को साधने की कोशिश की जा रही है। जसवंत सैनी एबीवीपी के साथ-साथ भाजयुमो में भी कई पदों को संभाल चुके हैं। पिछड़ा आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे हैं। शामली जिले के जिला प्रभारी का भी काम संभाला है। पिछड़ा वर्ग में दो उपाध्यक्ष हीरा ठाकुर और रघुनाथ चौहान को बनाया गया है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में समीकरणों को साधने के लिए भाजपा संगठन में कई और नियुक्तियां कर सकती हैं। सबसे खास बात है कि भाजपा पुराने और कद्दावर नेताओं को महत्व देने की कोशिश कर रही है। बता दें कि उत्तर प्रदेश के कई नेताओं ने पार्टी संगठन में विस्तार नहीं होने को लेकर नाराजगी जताई थी। हालांकि, यह बात भी सच है कि वर्तमान समय में हो रहे बदलाव कहीं ना कहीं चुनाव को देखते हुए किए जा रहे हैं।

पंजाब को असम, यूपी से ज्यादा रेमडेसिविर दिया गया: केंद्रीय मंत्री

नयी दिल्ली। (एजेंसी)।

केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कांग्रेस सरकार पर कोविड का टीका निजी अस्पतालों को बेचकर मुनाफाखोरी का आरोप लगाते हुए शुक्रवार को कहा कि पीएम-केयर्स के तहत पंजाब के लिए अतिरिक्त 41 ऑक्सीजन प्लांट मंजूर किए गए हैं। उन्होंने यह भी दावा किया कि केंद्र सरकार द्वारा पंजाब को असम और उत्तर प्रदेश से ज्यादा रेमडेसिविर दिया गया। भाजपा के राष्ट्रीय मुख्यालय में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने सहकारी संघवाद की सच्ची भावना के साथ पंजाब के लिए कई काम किए हैं। पुरी ने आगे कहा, पंजाब के लिए पीएम-केयर्स के तहत पहले से स्वीकृत 13 के अलावा 41 ऑक्सीजन प्लांटों को मंजूरी दी गई है। केंद्र द्वारा खरीदी गई दवा या टीके में उचित हिस्सा नहीं मिलने के विपक्षी शासित राज्य के आरोपों पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पुरी ने कहा, तीन राज्यों के विश्लेषण से पता चलता है कि पंजाब को प्रति हजार असम और उत्तर प्रदेश की आबादी की तुलना में अधिक संख्या में रेमडेसिविर आवंटित किया गया है। पुरी ने बताया कि समान जनसंख्या वाले असम में प्रति हजार जनसंख्या पर 323 रेमडेसिविर मिले जबकि पंजाब को 623 रेमडेसिविर मिले। उत्तर प्रदेश को प्रति हजार जनसंख्या पर 264 रेमडेसिविर इंजेक्शन मिले। उन्होंने पंजाब के लिए मोदी सरकार द्वारा किए गए कार्यों की एक श्रृंखला को सूचीबद्ध किया और कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्यक्तिगत रूप से और उनकी सरकार पंजाब सहित सभी राज्यों के लिए बहुत कुछ कर रही है। टीके से मुनाफाखोरी पर पुरी ने कहा, पंजाब सरकार ने कहा था कि उन्होंने कोविशील्ड की 4.29 लाख खुराक 13.25 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जिसकी औसत कीमत 309 रुपये प्रति खुराक थी। उन्होंने कोवैक्सीन की 1,14,190 खुराक भी 4.7 करोड़ रुपये में खरीदी थी, जिसकी औसतन प्रति खुराक 412 रुपये है। उन्होंने निजी अस्पतालों को 750 रुपये प्रति खुराक के लाभ पर टीके बेचे।

श्रीलंकाई मछुआरों ने भारतीय नौसेना पर लगाए गंभीर आरोप, भारत ने खबरों को दिया साफ झूठ करार

कोलंबो। (एजेंसी)।

भारत ने शुक्रवार को श्रीलंका के स्थानीय मीडिया में आई उन खबरों को 'साफ झूठ' करार दिया, जिनमें कहा गया था कि भारत की नौसेना ने कथित तौर पर श्रीलंका के मछुआरों के समूह के साथ मारपीट की है। भारत ने कहा कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। श्रीलंका के 13 स्थानीय मछुआरों के एक समूह ने दावा किया था कि मछली पकड़ने के जहाज 'थुशान 1' और 'थुशान 2' पर सवार होकर वे सात मई को समुद्र में उतरे थे और चार जून को ड़िएगो गार्सिया के निकट अंतरराष्ट्रीय जल क्षेत्र में भारतीय नौसेना ने उनके साथ मारपीट की। इनमें से दो मछुआरों ने बृहस्पतिवार को स्थानीय हीरू टीवी को बताया, ''हमने बताया कि हम मछुआरे हैं, इसके बावजूद उन्होंने हमसे मादक पदार्थ मांगे।'' भारतीय उच्चायोग ने मछुआरों के भारतीय नौसेना द्वारा उनके साथ मारपीट के दावे को खारिज किया। उच्चायोग की ओर से कहा गया, ''17 जून को मीडिया में आई खबरों में कहा गया कि भारतीय नौसेना ने श्रीलंका के मछुआरों के समूह पर हमला किया, जो साफ झूठ है। इस तरह की कोई घटना नहीं घटी।'' उच्चायोग ने एक वक्तव्य में कहा, ''भारतीय नौसेना एक बहुत ही अनुशासित एवं पेशेवर बल है, जो अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन परिपूर्ण तरीके से करती है।'' उसने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच मछुआरों से जुड़े सभी मुद्दों को स्थापित द्विपक्षीय प्रणालियों और समझौतों के जरिए मानवीय तरीके से सुलझाने के लिए भारत दृढ़ प्रतिज्ञ है।

मीडिया में कथित घटना की खबरें आने के बाद मत्स्यपालन मंत्रालय में सचिव इंदु रथनायक ने स्थानीय मीडिया से कहा कि रिपोर्ट की छानबीन के बाद इस बारे में भारत से बात की जाएगी। इससे पहले कई भारतीय मछुआरे आरोप लगा चुके हैं कि श्रीलंका सीमा के निकट मछली पकड़ने पर उन पर श्रीलंका की नौसेना ने हमला किया। मछली पकड़ते वक्त असावधानीवश एक दूसरे के जल क्षेत्र में जाने पर दोनों देशों के मछुआरे गिरफ्तार किए जाते रहे हैं। इस तरह की घटनाओं के बाद द्विपक्षीय संबंधों में मछुआरों का मुद्दा तनाव का प्रमुख विषय बन गया है। इस साल जनवरी में विदेश मंत्री एस. जयशंकर श्रीलंका आए थे और उन्होंने मत्स्यपालन मंत्री डगलस देवानंद से मुलाकात की थी। जयशंकर ने मछुआरों से जुड़ा मुद्दा उठाया था और मत्स्यपालन के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग की समीक्षा की थी।

स्वामी, मुद्रक व् प्रकाशक : सुरेश मौर्या द्वारा अष्ट विनायक ओफ़्सेट एफपी,149 प्लोट 26 खोडीयारनगर, सिद्धिविनायक मंदीर के पास , (भाटेना) हो.सो अंजना सुरत
गुजरात से मुद्रित एवं 191 महादेव नगर उधना सुरत गुजरात से प्रकाशित संपादक :सुरेश मौया (M) 9879141480 RNI No.:GUJHIN/2018/751000 (Subject to Surat jurisdiction)